evil law will begin to be used for evil purposes for which it is meant. Today you are seeing that the use of this evil law is becoming more and more widespread. For example, it is being used in Tamil Nadu. Against whom? It is being used in Tamil Nadu against whom? It is being used against people who till the other day were sitting there peacefully negotiating with the Government and its representatives. When the talks break down, you hold them under the National Security Act. You are creating monsters all over the country and these monsters you have created can only be tamed by your understanding of how those monsters were created, by retracing some of the tragic steps which you have taken in history. The Punjab problem is the problem created by corrupt politicians and unless those corrupt politicians go back upon their corruption the Punjab problem will not be solved. This law is an ignoble law. Unless you are prepared to give up this law and adopt some civilised methods of dealing with the situation in Punjab, I am afraid the Punjab problem will live with us and live with us unless this wooden-headed Government is displaced. Thank you.

STATEMENT BY MINISTER

Damage to life and property caused by earthquake in Bihar

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, भूकम्प के बारे में मुझे स्टेटमेंट देना है । इस स्टेटमेंट की हिन्दी की कापियां तो उपलब्ध हैं लेकिन अंग्रेजी की कापी एक डेढ़ घंटे में उपलब्ध हो सकेगी । अगर केवल हिन्दी से काम चल सकता है तो मैं अभी स्टेटमेंट दे दूं और अंग्रजी की कापी भी साथ ही चाहिए तो यह स्टेटमेंट साढ़े चार बजे तक हो पाएगी ।

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): I am on a point of order. Sir, on previous occasions when the Minister came with a statement, only the English copies were circulated. But the Members agitated because they had not received the copies in Hindi. The Minister was asked to resume his seat. The other business was taken up in the meantime. Sir, what has happened today? Due to the pressure being exerted by some of the hon. Members, they have not cared to distribute the copies of the statement in English. Therefore,....

श्री भजन लाल : मेरी बात आप समझे नहीं । अंग्रेजी की कापी आने वाली है । उस में एक डेढ घंटे का समय लगेगा ।

SHRI V. GOPALSAMY: I have not concluded.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : गोपालसामी जी कह रहे हैं कि तब तक आप रोक दीजिए । यह सरकार की असफलता है (**व्यवधान**)

SHRI M. S. GURUPADASWAMY (Karnataka): Sir, the behaviour of the Minister is creating a division in the House. I am not against anything at all. I am just drawing the attention of the Minister to one thing. If he wants to make a statement, he should prevent such feelings being generated amongst certain members here. They should bring copies of the statement both in English and Hindi simultaneously. There is nothing wrong in it. I am making a suggestion. Why is this being done? Why are you creating an ugly situation here unnecessarily?

श्री भजन लाल : कोई ऐसी बात मैंने नहीं कही । मैं तो कह रहा था (**व्यवधान**)

SHRI V. GOPALSAMY: I have not completed my point of order.

श्री भजन लाल : मैंने कहा है कि अंग्रेजी की कापी एक डेढ़ घंटे में आएगी इसलिए टाइम चाहिये । (**व्यवधान**) ऐसा कुछ नहीं है । कहीं आप यह न समझे कि सरकार ने

[श्री भजन लाल]

स्टेटमेंट नहीं दिया इसलिए मैंने यह कहा कि हिन्दी की कापी मेरे पास है लेकिन अंग्रेजी की आने वाली है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : हिन्दी और अंग्रेजी साथ-साथ रखनी चाहिए ।

SHRI V. GOPALSAMY: Mr. Vice-Chairman, Sir, I have not completed. In the mean time the Minister has stood up. I have not completed my point of order.

ठाकुर जगत पाल सिंह : (मध्य प्रदेश) हम लोग इतने सेंटीमेंटल नहीं होते हैं लेकिन अंग्रेजी की कापी मिलने में थोड़ी देर हो जाती है तो आप इतने सेंटीमेंटल क्यों हो जाते हैं ।

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : मेरा पाईंट आफ आर्डर यह है कि हमेशा पहले अंग्रेजी की कापी आती है । यह जरूरी नहीं है कि हिंदी के साथ अंग्रेजी आये या अंग्रेजी के साथ हिंदी आये (**व्यवधान**) आनरेबुल मेम्बर्स ये ऑब्जेक्शन . . (**व्यवधान**) जो उठा रहे हैं ये पोलिटिकल परपज के लिए उठा रहे हैं इसलिए ये सारे ऑब्जेक्शंस सस्पेंड कर दिये जायें . . (**व्यवधान**)

SHRI V. GOPALSAMY: Because there is no copy of the statement in English, I am put into difficuly. I cannot understand . . (*Interruptions*).

SHRI JASWANT SINGH (Rajasthan): Sir, my point is really not on account of the Government not coming forward with the statement in the required two languages. My point is about the treatment of the House with contempt and in a manner which takes it for granted.

श्री भजन लाल : आप इतने सीनियर मेम्बर हैं । इसमें क्या पोलिटिकल है ? . . . (**व्यवधान**)

SHRI JASWANT SINGH: You cirulated to us an agenda saying that the statement will be made by the minister at 12.30 p.m. you changed it to 1.30 p.m. Some of us might suffer in the process but that is nobody's brother. (*Interruptions*).

श्री भजन लाल : अंग्रेजी में नहीं आई इस लिए कहा था . . . (**व्यवधान**)

SHRI JASWANT SINGH: Now the Hon. Minister comes forward here saying that it has to be changed to 4.30 p.m. And a copy of the English statement comes only now. Earlier he had a suggestion to make that it be shifted to 4.30 p.m. Sir, please do not take the House for granted. Please do not take the House so much for granted.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. R. K. PODDAR): The Government should be more careful in the future so that the statements in the two languages come at the same time.

श्री भजन लाल : जैसा कि माननीय सदस्य जानते है 21 अगस्त, 1988 रविवार के दिन सुबह 4 बजकर 39 मिनट पर देश के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भागों में एक प्रबल भूकम्प आया । इस भूकम्प की प्रबलता रिएक्टर स्केल पर 6.5 थी । भूकम्प का एपी सैन्टर बिहार–नेपाल सीमा के पास और दरभंगा के उत्तर-पूर्व में लगभग 70 किलोमीटर पर था । भूकम्प के केन्द्र की गहराई 20 किलोमीटर थी । इसके केवल 15 मिनट बाद, 4 बजकर 54 मिनट पर उसी केन्द्र से एक और भूकम्प का झटका लगा जो पहले वाले से कम था ।

2. इस भूकम्प का मुख्य प्रभाव बिहार पर पड़ा । बिहार में मुख्य क्षति दरभंगा, मधुबनी और मुंगेर जिलों में हुई है । भूकम्प का असर सहरसा, मोतिहारी बतिया और हजारीबाग जिलों पर भी पड़ा है । बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम और त्रिपुरा में भी भूकम्प का असर पड़ा । पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग कालीपांग, कुरस्यांग और कलकत्ता में भी झटके महसूस हुए । परन्तु व्यक्तियों की मृत्यु

की सूचना केवल बिहार से ही मिली है। राष्ट्रीय राज-मार्गों को नुकसान पहुंचने की कोई सूचना नहीं मिली है। इसी तरह किसी भी मुख्य सिंचाई योजना को क्षति नहीं हुई है। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार बड़े प्रतिष्ठानों को भी नुकसान नहीं हुआ है।

3. भूकम्प की सूचना पाते ही प्रधानमंत्री जी बिहार के मुख्य प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर कल तुरन्त निकल पड़े। वे अपने साथ मुझे और शहरी विकास मंत्री श्रीमती मोहसिना जी और स्वास्थ्य मंत्री श्री मोती लालजी वोरा को भी ले गये थे। पटना हवाई अड्डे पर उन्होंने बिहार के मुख्य मंत्री और उनके सहयोगियों से विचार-विमर्श किया। तत्पश्चात् वे दरभंगा, मधुबनी और मुंगेर गये। इन सभी स्थानों पर वह बहुत लोगों से मिले और उनका दुख-दर्द सुना। इनमें कई वह लोग भी थे जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहर पहुंचे थे। उन्होंने हेलि-काप्टर की नीची उड़ान से मधुबनी जिले के सबसे अधिक क्षतिग्रस्त तीन ब्लाकों का निरीक्षण किया। यह क्षेत्र झंझारपुर, अंधराठडी और राजनगर उप-खंडों में पड़ते हैं। उन्होंने इन क्षेत्रों का मुख्य नदी के बान्धों का भी निरीक्षण किया। दरभंगा और मुंगेर में प्रधान मंत्री जी ने अस्पतालों में भर्ती घायलों से मुलाकात की। दरभंगा में वे उस मेडिकल कालेज के छात्रावास को भी देखने गये, जिसका काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने उस मदरसा को भी देखा, जो गिर गया है। जीवन-हानि, बड़ी संख्या में घायलों और सम्पति के नुकसान को देख कर प्रधान मंत्री व्यथित और द्रवित हुए।

4. कल रात्रि के 9 बजे तक बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 164 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और 1209 व्यक्ति घायल हुए हैं। ऐसी सम्भावना है कि ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों से सूचना प्राप्त होने पर यह संख्या बढ़ भी सकती है, परन्तु लगता है कि क्षति प्रकोप उस स्तर का नहीं होगा जैसी कि पहले आशंका बनी हुई थी।

5. दौरे से लौटने के पश्चात् पटना में प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से 30 लाख रुपये देने की घोषणा की। इससे मृतक परिवार के सदस्यों को 10 हजार रुपये की सहायता दी जायेगी। घायलों और जिन लोगों के मकान गिरे हैं, उन्हें भी सहायता दी जायेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिये स्वयं सेवी संस्थाएं आगे आयेगी तथा जन-सहयोग प्राप्त होगा।

6. प्रधानमंत्री जी ने अस्पतालों में चिकित्सा प्रबन्ध के बारे में भी पूछताछ की। मुंगेर में दवाओं की कमी बतलाई गई। प्रधानमंत्री जी की सलाह पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री पटना में रुक कर चिकित्सा प्रबन्ध सुनिश्चित कर रहे हैं।

7. घरों तथा सार्वजनिक सम्पति को पहुंचे नुकसान के बारे में पूर्ण ब्यौरा संकलित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इस कार्य को जल्दी निपटाने के बारे में राज्य सरकार, केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय को निर्देश दिये हैं और यह चाहा है कि जिन कमजोर-आर्थिक वर्गों के मकान भूकम्प से क्षतिग्रस्त हुए है, उन की सहायता के लिए एक विशेष योजना बनायी जाये।

8. प्रधानमंत्री जी ने भूकम्प के बारे में सूचना मिलते ही संबंधित विभागों और मंत्रालयों को सचेत किया कि वे स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क बनायें जो सहायता कार्य में संलग्न है। कृषि मंत्रालय ने सभी प्रभावित राज्यों से रविवार को ही सम्पर्क स्थापित किया और क्षति तथा राहत कार्यों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की।

9. कृषि मंत्रालय ने आपत्ति नियोजन समिति का गठन किया जिसमें अन्य सभी संबंधित मंत्रालय सम्मिलित हैं। रक्षा मंत्रालय ने राहत कार्य के लिए सेना के 5 दस्ते भेज दिये हैं। कल एक इंजिनियरिंग दस्ता भी हवाई जहाज से भेजा गया है। भारत सरकार ने 8 चिकित्सकों, विशेषज्ञों का एक दल नई दिल्ली से आवश्यक दवाइयों के साथ बिहार भेज दिया है।

[श्री भन ल.ल]

10. इस बारे में आश्वासन प्राप्त कर लिया गया है कि बिहार के प्रभावित क्षेत्रों में समुचित मात्रा में खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं का भण्डार उपलब्ध है । पेट्रोलियम पदार्थों का भी कोई कमी नहीं है ।

11. कृषि मंत्रालय की आपत्ति-नियोजन समिति की बैठक हर रोज हो रही है । केबिनेट सचिव की अध्यक्षता के सचिवों की समिति ने भी कल पूरी स्थिति का जायजा लिया और इसकी बैठक भी नियमित रूप से होती रहेगी ।

12. यह सर्वविदित है कि ऐसे भूकम्प के पश्चात कुछ अन्य झटके भी आते हैं । इस बारे में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

13. इस समय हमारे सम्मुख घायलों का उपचार, क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत तथा प्रभावित लोगों का पुनर्वास सबसे प्रमुख कार्य हैं । प्रधानमंत्री जी के दौरे से जनसाधारण का मनोबल ऊंचा हुआ है और उनका आत्म-विश्वास बढ़ा है ।

14. ऐसी प्राकृतिक दुर्घटना के लिए इस सदन की ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की सहानुभूति उन लोगों के लिए उमड़नी स्वाभाविक है, जो भूकम्प से प्रभावित हुए हैं । मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारा राष्ट्र इस चुनौती का डट कर सामना करेगा । मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सरकार हर सम्भव पर्याप्त, प्रभावी सहायता के लिए कदम उठा रही है, और किसी प्रकार की भी कठिनाई उन लोगों के सामने आगे सरकार नहीं आने देगी और उन मुसीबतजदा लोगों की सरकार पूरी तरह से मदद करेगी ।

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Sir, there is some discrepancy between what is mentioned in the statement here and what has been reported in the Press and the official media, the radio and television. Earthquake is one on which there is no human control. It is not like an epidemic or a thing like floods where there is human control. Sir, it is reported that in this earthquake, in Bihar alone, several hundred people have lost their lives and thosands have been injured. But in this statement a different figure is given. Last evening, the Chief Minister of Bihar also asserted that only 164 have lost their lives and 1209 injured. I would like to know on what basis the Chief Minister of Bihar and the Central Government came to the conclusion that only 164 people were killed and 1209 injured. But the report in the Press and other media puts the death toll at a much higher figure. As I said earlier it is not like an epidemic or floods; there is no human control over earthquakes. Therefore, at least in such a thing as this, there is no need for suppressing facts. Everybody in the country has a right to know the facts as to the extent of damage caused in terms of property as well as in terms of human life. Therefore, I would like to have the factual figure in regard to the total death toll and the number of injured.

Anoher figure which I would like to have is the number of people rendered shelterless. Of course, the Government may not be able to give the precise figure. But an approximate figure can be given in regard to the number of people rendered shelterless in Bihar.

Then Sir, some other States have also experienced the tremor, some neighbouring States. I would like to know whether the Government have made any assessment of the damage caused in these States in terms of property as well as human lives lost. I would like to know whether the Government have this figure.

In regard to rendering assistance, financial assistance, to the people who have suffered, of course, the Prime Minister has granted Rs. 30 lakhs from the Prime Minister's Relief Fund. Other assistance is also being provided. But I would like to know what comprehensive scheme the Govern-

ment are going to take up to provide rehabilitation to these people, to the people who have been injured and who have been rendered shelterless. Some money has been allocated. But it is not clear what other types of assistance will be given to these people. I woul dlike to know whether the Government are thinking of rendering assistance to the other States also where some damage has been caused.

Lastly, I would like to know whether, in India, we have developed any scientific method to predict earthquakes. I was informed that in Mexico they have developed what is called the seismic grid method using which they were able to predict the tremor in Mexico in 1985. Taking advantage of this prediction, they took precautionary steps before the tremor actually occurred. I would like to know whether, in India, some such method or device has been developed to predict tremors. It has also been reported that one Mr. Arun Bapat, a seismic scientist in India. informed in October, 1985, the International Centre for Integrated Mountain Development that such a tremor was to occur in Bihar, along the Indo-Nepal border, in 1988. Is it a fact that Mr. Arun Bapat gave such a warning and, if so, whether the Government took that warning seriously and took some precautionary measures to face this calamity?

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA (Delhi): Mr. Vice-Chairman, Sir, while welcoming the fact that very prompt action was taken both by the hon. Prime Minister and the Ministers concerned in this matter and relief offered, I would like to ask the hon. Minister whether he is aware that the North-East area of India is, according to scientists, very highly earhquake-prone area. It is said that two-thirds of India in the Northern States is in constant danger of tremors. In fact it has been brought out by scientists that on an average 625 earthquakes from lesser to moderate intensity occur annually in the North-Eastern region, making it one of the most seismologically active zones in the whole world. I would like to know, as my hon. colleague from the other side had asked the hon. Minister, whether any scientific studies are being carried out in a very systematic manner to find out whether what countries like Mexico and China have developed as some method of prediction of these earthqrakes can be adopted by India and whether those attemts have been successful and helpful in trying to have a prediction as well as some preventive measures being taken by them.

The hon. Minister has in para-2 indicated that there was no damage to the National Highways. I would also like to know whether there has been any damage to railway tracks and other means of locomation, also whether there has been some damage to communication systems like telephones and others which might make the relief measures more difficult.

Also, there is a long history of very severe types of earthquakes which have occurred in India over many many years. Therefore, the Government should be in a position to have a systematic plan for meeting such calamities. I would like to know from the hon. Minister whether any such long-term plan has been made by the Ministry and whether the relief measures that he has outlined are going on satisfactorily. Thank you.

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष जी, स्वतंत्रता के पश्चात् की यह भूकम्प की सबसे बड़ी त्रासदी है और स्वाभाविक रूप से इसका सबसे अधिक परिणाम बिहार पर होने के कारण सारा देश बिहार की जनता के साथ अपनी संवेदना प्रकट करता है वैसे यह संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ या दोषारोपण का समय नहीं है फिर भी मैं निश्चित रूप से कहा सकता हूं कि इस त्रासदी के बारे में इससे अधिक विवरण

[श्री प्रमोद महाजन]

देनेवाला वक्तव्य सरकार कर सकती थी। इस विवरण का अधिकांश हिस्सा माननीय प्रधान मंत्रीजी के दौरे का विवरण देने में चला गया है। माननीय प्रधान मंत्रीजी तुरंत गए यह अभिनंदनीय है, लेकिन अन्य बातें इसमें सही नहीं हैं और इस दृष्टि से मैं मंत्री महोदय से कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा।

वक्तव्य के चौथे परिच्छेद में यह कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों तथा दूरदराज इलाकों से सूचना प्राप्त होने पर मृतकों तथा घायलों की संख्या बढ़ सकती है परंतु लगता यह है कि क्षति-प्रकोप उस स्तर का नहीं होगा जैसीकि पहले आशंका बनी थी। अब इन दोनों वाक्यों के अर्थ को मिलाकर मैं यह जानना चाहता हूं कि पहली आशंका क्या बनी थी ? उस आशंका के बनने के क्या आधार थे जिसके कारण कि आपने कहा कि क्षति अधिक होगी ? अब आपके पास ऐसी कौनसी जानकारी आई है कि उससे आपको लगता है कि क्षति कम होगी ? जब आप ही स्वयं अपने वक्तव्य में कहते हैं कि दूर-दराज के इलाकों में सूचना अभी प्राप्त होनी है, होने पर संख्या बढ़ सकती है, एक वाक्य में आप कहते हैं कि संख्या बढ़ सकती है और दूसरे वाक्य में कहते है कि संख्या इतनी ही रह सकती है, तो अपने आप में यह एक स्पष्ट वक्तव्य नहीं हुआ। तो मैं यह नही जान सका हूं कि आखिर बिहार की इस नैसर्गिक दुर्घटना में संख्या को कम या ज्यादा करने से न किसी को लाभ होगा न नुकसान है और इसलिए जिस प्रकार की स्थिति है, और होने की संभावना है इस के बारे में अगर राष्ट्र के सामने स्पष्ट चित्र दिया जाए तो उससे सरकार को और राष्ट्र को जनता को इस समय बिहार की जनता की मदद करने में पूर्ण सहायता हो सकती है। इसलिए सबसे पहले मैं मंत्री महोदय से यह स्पष्टीकरण जानना चाहूंगा कि मृतकों की और क्षति की संख्या सम्बंधी जो विरोधाभास आपके वक्तव्य में है यह क्यों है और इसपर आपका स्पष्टीकरण क्या है ?

दूसरी बात प्रधानमंत्री कोष से हमने हर मृतक के लिए 10 हजार की राशि घोषित की है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह राशि केवल आपात रूप में घोषित की गई है ? क्योंकि रेल दुर्घटना में या हवाई जहाज की दुर्घटना में जहां यात्रियों का कोई दोष नहीं होता, ऐसे समय में हम 1 लाख रुपए की राशि उन्हें देते हैं। यहां भी जितने मृतक हैं उनका अपना कोई दोष नहीं है और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री कोष द्वारा घोषित 10 हजार की राशि, क्या यह आपात रूप में केवल तुरन्त दी जाने वाली राशि है, या इसको बाद में बढ़ाने की संभावना है ? मैं तो यह मांग करता हूं कि जिस प्रकार से रेल या हवाई दुर्घटना में हम एक लाख रुपए की राशि प्रति मृतक व्यक्ति देते हैं क्या उसी के आधार पर सरकार विचार करके इस राशि को बढ़ाने की कोशिश करेगी ?

दूसरे इसके साथ जैसे केन्द्र सरकार की ओर से मदद होगी, वैसे ही सारे राष्ट्र की ओर से, स्वाभाविक रूप से विभिन्न राजनीतिक दल और स्वयंसेवी संस्थाएं भी यहां मदद करने के लिए आगे आएंगी। बिहार में सभी विरोधी दलों की ओर से एक मांग रखी गई है कि इसमें जो भी राहत कार्य हों, और हम सभी जानते हैं, हमारे समाज का यह दोष है मैं किसी व्यक्ति को दोष नहीं देता, कि ऐसे राहत कार्यों में भी बाद में भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है। इस भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए सभी राजनीतिक दलों की एक सर्वदलीय समिति बनाकर क्या हम इस प्रकार का विचार कर सकते हैं कि राहत कार्यों पर इसका नियंत्रण होगा जिसके कारण राहत कार्य सुचारू रूप से चलें। इसके पहले 1934 में जब इस प्रकार का बहुत बड़ा भूकम्प आया था बिहार में तब इस प्रकार की सर्वदलीय समिति की स्थापना हुई थी और सबने मिलकर इसके साथ जूझने का प्रयास किया था। इस विरोधी दल की संयुक्त समिति और उसके साथ सत्तारूढ़ दल के मैम्बर यह सारे मिलकर एक सर्वदलीय समिति बनाएं, इस पर सरकार का क्या विचार है ?

जैसा आपके ही वक्तव्य में कहा गया है कि प्रधानमंत्री जब स्पताल में गए तो मुंगेर में दवाओं की कमी बतलाई गई । स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री एक दिन के लिए, दो-तीन अस्पतालों में ही गए । जहां वे गए, वहां भी दवाओं की कमी थी, जहां वे पहुंच नहीं पाए होंगे स्वाभाविक रूप से वहां भी दवाओं की कमी होने की पूरी-पूरी संभावना है। तो इस प्रकार से, जहां भी इस प्रकार की घटनाएं हों, वहां जितने भी अस्पताल है, इन अस्पतालों में किस प्रकार से दवाओं की व्यवस्था आप करना चाहते हैं, मैं यह भी स्पष्टीकरण चाहूंगा ।

बिहार में छोटी-बड़ी सिंचाई परियोजनाएं है । अब सिंचाई परियोजनाएं ही भूकम्प का कारण हैं या नहीं, मैं इस पर नहीं जान चाहता, लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि इतने बड़े भूकम्प का सिंचाई और सारी परियोजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है ? बड़ी योजनाओं पर क्या पड़ा है, छोटी योजनाओं पर क्या पड़ा है और कभी क्या दरार आने की संभावनाएं हैं जिससे कि यह त्रासदी और भी अधिक बढ़ती जाए । तो इस दिशा में, इस प्रकार की सिंचाई योजनाओं पर किस प्रकार का परीक्षण, निरीक्षण किया जा रहा है, इसकी क्या योजना है, यह भी मैं स्पष्टीकरण के रूप में जानना चाहूंगा ।

उसी के साथ अपने वक्तव्य में आपने कहा है कि यह सुनिश्चित है कि ऐसे भूकम्प के पश्चात् कुछ अन्य झटके भी आते हैं, इस बारे में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है । अब थोड़ा अपने आप में, जैसे मैंने पहले कह दो वाक्य आपके
2 P.M. विरोधाभास के थे, वैसे ही यह वाक्य आपके विरोधाभास का है क्योंकि जब आप स्वयं अपने वक्तव्य में कहते हैं कि इस प्रकार के भूकम्प के बाद अन्य झटके आने की संभावना वैज्ञानिक बताते हैं उसमें घबराने की बात नहीं है तो क्या आप यह बता सकते हैं कि घबराने की बात इसलिए नहीं है कि उसके बाद कम क्षमता के झटके आते हैं, इससे जनता का मनोबल ऊंचा हुआ है । आपने 'घबराने की बात नहीं है' शब्दों का उपयोग किया है तो आप जनता को आश्वस्त करें, उसको किसी प्रकार से धीरज बंधाएं कि किस कारण उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है । इसलिए नए झटके आने की संभावना के बारे में मंत्री महोदय क्या कहना चाहेंगे, उस दृष्टि से इसका क्या वैज्ञानिक रूप में विवेचन करा सकेंगे ?

उपसभाध्यक्षजी, इसके साथ ही मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत हर वर्ष 2.5 सेंटीमीटर उत्तर की ओर जा रहा है और उत्तर में हिमालय भूकम्प का ओर क्षेत्र बन चुका है और वैज्ञानिकों का यह कहना है कि धीरे धीरे दो तिहाई भारत इस चपेट में आ सकता है । 1985 में विश्व के एक बड़े भूकम्प विज्ञानी एम० टाइडमैन ने हिन्दुस्तान में इस प्रकार के भूकम्प आने की भविष्यवाणी की थी और उन्होंने यह भी कहा था कि दिल्ली समेत उत्तर भारत में इस प्रकार के अनेक भूकम्प के झटके आने की संभावना है । इसके साथ ही भारत के एक वैज्ञानिक अरुण बापट ने भी इसी प्रकार का संकेत दिया था । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भूकम्प की पूर्व सूचनायें मिलने की वैज्ञानिक रीति या पद्धति की सरकार को जानकारी है ? मैं जानता हूं कि इसमें वैज्ञानिकों में मतभेद हैं, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि सम्भावित स्थान बता सकते हैं, समय नहीं बता सकते हैं, लेकिन चीन में कहीं-कहीं इस प्रकार का अनुभव आया है कि भूकम्प आने से पहले भूगर्भीय स्थिति में और भूगर्भ में जन्तुओं में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखे गये हैं, जैसे कि दो वर्ष पहले आये चीन के भूकम्प में सांप की आवाज में विशेष परिवर्तन देखा गया, उस परिवर्तन को देखकर इसके सबंध में भविष्यवाणी की गई थी और कुछ कदम उठाये गये थे । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने कोई वैज्ञानिकों की समिति बिहार भेजी है जो इसका अध्ययन करे कि क्या आगे भी लोगों के इस भूकम्प की चपेट में आने की संभावना तो नहीं है ? क्या इसकी पूर्व सूचना थी और आप इस बारे में क्या करने जा रहे हैं ?

[श्री प्रमोद महाजन]

इसके साथ ही भूकम्प की तीव्रता दोनों जगहों में क्या थी क्योंकि भूकम्प दिल्ली में भी आया और बिहार में भी, लेकिन दिल्ली में उतना नुकसान नहीं हुआ जितना बिहार में । वैज्ञानिकों का यह कहना है कि समान भूकम्प होने के बाद भी दिल्ली में इसलिये नुकसान नही हुआ कि दिल्ली शहर चट्टान पर खड़ा है और बिहार में नुकसान इसलिये हुआ कि बिहार भूगर्भीय दृष्टि से रेत पर खड़ा है। अगर भौगोलिक कारण से यह बना हो तो मैं जानना चाहूंगा कि बिहार की भौगोलिक स्थिति के कारण क्या उत्तर भारत में रहने वाले भविष्य में इस प्रकार की योजनायें बना कर इस त्रासदी से बचाये जा सकते है, इसके बारे में भी क्या सरकार सोच रही है ? यदि सोच रही है तो उसकी भी जानकारी दें ।

SHRI YASHWANT SINHA (Bihar): Mr. Vice-Chairman, Sir, it is with tremendous sadness that I get up to seek clarifications from the Minister on the statement which he has placed before the House.

Bihar is a cursed State. It is only last week that we discussed in this House two man-made tragedies of great magnitude—the massacret in Jehanabad and the sinking of the ferry between Manihari Ghat and Sahebganj. Now, unfortunately, it is a curse of God which seems to have visited that unfortunate State from which I happen to come. One would have expected that when we were faced with a gruesome natural tragedy of this proportion, all of us, whether on this side of the House or, more so, on that side of the House, would have refrained from injecting any element of politics. This is not a party matter. But I am very sorry to point out that this statement is a political statement. It is not a statement which we expected from the hon. Agriculture Minister to be placed before this House. I am very angry on this and I register my protest on it. What does the Minister mean when he says: "As a result of the Prime Minister's visit, the people's spirits are high and their self-confidence fortified." What is the meaning of this one sentence? I am not given to being emotional, but I would like to point out that..(Interruptions) Just a moment. (Interrupions)

SHRI V. GOPALSAMY: The Member has a right to make his submission Why are you getting agitated?

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: The Prime Minister is the Prime Minister of the country. What is wrong in it?

SHRI V. GOPALSAMY: The Prime Minister is not a God who has jumped from the heavens.

SHRI YASHWANT SINHA: Anybody who has the slightest idea of the psychology of the victims of an earthquake, knows that one shock is not enough, as the Government itself says, as the newspapers say, as the official media says, many more shocks are expected. They have, in fact, taken place. What is the psychology of the people? The psychology of the people is that they ran away from their homes. Even those whose homes have not been devastated, which have not fallen, which have not been damaged, even those people would refuse to spend their nights, to spend their days, to spend their time inside those houses, because they are in mortal fear that they are in danger of another earthquake. Therefore they do not want to take any chance with their life. I am not saying that the hon. Prime Minister of the country is responsible for the earthquake. But I also say with equal emphasis that it is not within the power of the Prime Minister to prevent an earthquake from taking place. It is not a Prime Ministerial visit or any Ministerial visit or any visit by a leader of the Opposition, which will create that necessary confidence in the people to enable them to stay in their houses. Therefore, this kind of Statement should have been best avoided.

Now a point has been raised in regard to the casualties. I share the concern of the members. I cannot see any reason why the Government should be interested in trying to minimise the damage caused and the loss of human life in this tragedy. We are not blaming the Government for this earthquake. But why are they so keen on saying that at 9 p.m. only 164 persons had died? At 10 p.m. so many people were dead. We all know that a tragedy of enormous proportions has taken place in that part of Bihar and a number of people have been killed not only in the towns and cities, but also in the far-flung rural areas. Now, yesterday the Chief Minister of Bihar was — I heard him on the television — saying this is being exaggerated. He is complaining against his own officially controlled media. What is the meaning of this? Why are they interested in minimising this tragedy? If they do, as my friend has said, then the relief, which the rest of the country wants to send to Bihar, is going to be affected. I would not like this tragedy to be exaggerated, but I would like the truth to come out so that the people from all over the country, who have sympathy for that unfortunate State today, could send adequate relief supplies to Bihar both in terms of money as well as in kind and through men and women.

Now, the Minister has said: Rs. 10,000 will be given to each family of the deceased. This is from the Prime Minister's Relief Fund. What is the amount which will be made available from the Chief Minister's Relief Fund? What is the amount of money which will be made available from other relief funds, which might be at the disposal of the Government? The other clarification which I would like to ask is that the Minister in his statement in paragraph 7 says "... a Special Scheme for assistance to the economically weaker sections whose dwellings have been seriously damaged by the earthquake will be started." It is not merely a question of the specially weaker sections. Naturally, we must have a scheme for them where we should be able to help hundred per cent so that they can build their houses. But simultaneously I would like to say, Mr. Vice-Chairman, that for other sections who do not come in the category of economically weaker sections, we must be able to make a provision, a special facility should be made available through the banks, a special counter should be opened where these people can go and get housing loans from the bank or from HFDC or HUDCO or any other organisation or nationalised banks. They should make loans available to these people for building their houses or repairing their houses whose houses have been damaged and who do not come in this category.

Then, the third thing is that under these circumstances a number of houses have been damaged, they have been demolished and people are subjected to this fear psychosis. A very large number of people in terms of lakhs, all of them are out in the streets of Bihar today. May I know from the Minister what arrangements has the Government made to provide shelter to them?

I would have expected the Minister to say in this statement that hundreds and thousands of army tents and other kinds of quickly assembling dwelling units should have been rushed to Bihar so that temporary relief, temporary shelter could be provided to these people who are shelterless. This the Minister will do well to point out at this point of time.

The other is that there is a need— because there is no mention here — for providing free kitchens in all the affected areas who have lost everything. They cannot cook. They have no utensils. The Government in consultation with all the other agencies who are engaged in this task should

provide immediately a number of kitchens so that they can provide succour and relief to these people.

Finally, I would like to say that in this hour of tragedy in which my State is plunged, one would have expected that the Government would immediately announce the constitution of an all party, all organisation, all comprehensive relief committee. To my mind, Sir, the Government will be failing in its duty, it will be showing its partisan attitude if it does not constitute at the State level and at the Central level immediately an all party all organisation, all comprehensive relief committee so that relief is not merely the hand-maid of the Government. It is something in which everybody is enabled to participate and relief is really taken to those who need most. Thank you.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, the statement issued after 57 hours of the tragedy is very vague. It is stated that 164 casualties were there by 9 P.M. yesterday whereas the State-owned T.V. and All India Radio announced that the casualties were much more than 300. The relief announced by the Prime Minister is much less. The Chief Minister of Andhra Pradesh as well as the Chief Minister of Haryana are there now and Karnataka putting together, I hope the target fixed will be reached and all the three States have announced Rs. 5 lakhs towards relief from each State.

There is an acute seismic zone stretching from Indonesia and Burma to Pakistan, Afghanistan, West Asia and the Mediterrancan including the northern parts of the country. In view of these recurrent earthquakes that are occurring, are there any new building regulations, zoning regulations? Is there innovative modern building technology that is offered to construct in these areas? The facts revealed in the statement and figures, are much less than already announced in the newspapers. The details of the rescue operations and the measures that they are contemplating are not mentioned here. So, I would like to seek clarification from the hon. Minister as to what relief measures as well as mode of operations are taking place. The last clarification I would like to seek from the hon. Minister is that in such natural calamities, instead of leaving the entire burden on the State Government since it is a national tragedy — let the nation came to the rescue of the State and without deducting anything from the State Plan assistance, let the entire amount be granted by the Centre.

[उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश) मालवीय पीठासीन हुये।]

श्री गुलाम रसूल मट्टू: (जम्मू और काश्मीर) : जनाब वाइस चेयरमैन, मैं अपनी तरफ से अपनी पार्टी की तरफ से इस हाऊस के जरिये इस अफातेसमावी पर उन लोगों को जो दुख हुआ है जो मरे हैं, हमदर्दी का पैगाम भेजता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इस हाऊस की तरफ से उनको हमदर्दी का पैगाम भेजा जाये।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : कल हो चुका है।

श्री गुलाम रसूल मट्टू : जनाबेआला अर्ज यह है कि अफातेसमावी जो आते हैं वह किसी आदमी के बनाये हुये नहीं होते हैं, खुदा की तरफ से आते हैं। देखना यह होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन उसके बाद जब यह अफातेसमावी आ जाये तो क्या करे और इस हाऊस को उसी की तरफ ही ध्यान देना है। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ने यह खबर पाते ही परसों एलान कर दिया कि मैं सोमवार को वहां जाऊंगा। सवाल यहां उठाया जाता है कि प्राइम मिनस्टर के वहां जाने से क्या होगा। यह ऐसा ही वाक्या है कि किसी के घर में रिश्तेदार के घर में अगर कोई मौत का वाक्या होता है तो सैकडों आदमी वहां उनको ढाढ़स बंधाने के लिये जाते हैं।

इस तरह से हकूमत के सरबरा का यह फर्ज होता है कि वहां जाकर उन लोगों को ढाढस बंधाये और यह भी एक तरीका होता है कि वहा जा कर देख ले कि किन-किन चीजों की उनको जरूरत है और उनके होते हुये वह चीजें उनको जल्दी से पहुंच जाती है। तो यह कहना कि प्राइम मिनिस्टर वहां क्यों गये तो मेरा ख्याल है कि यह ज्यादती है। (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : यह तो किसी ने नहीं कहा है।

श्री गुलाम रसूल मट्ट : : मैं वाइस चेयरमैन साहब यह पूछना चाहता हूं कि एक दो बातें हुई है जिनसे जरा मुश्किल पैदा हुई है। आज सुबह जो आल इंडिया रेडियो से खबरों में कहा गया मैं उसकी तरफ वजीर साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज सुबह की बात है आल इंडिया रेडियो ने कहा कि 164 आदमियों की मौतें हुई हैं यह भगवत झा आजाद कहते हैं मगर हमारी सरकार का अंदाजा है कि चार सौ मौतें हुई हैं। अब आल इंडिया रेडियो जो है वह हमारा अपना है। अगर आल इंडिया रेडियो से दोनों वर्शन आ जाते हैं कि आफिशियल फिगर्ज 164 है और अनआफिशियल 400 हैं तो लोगों के मन में हैजना पैदा हो जाना लाजमी है। तो मैं गवर्नमेंट से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इस मसले को आल इंडिया रेडियो और टेलीविजन वालों से उठाया है। अगर सरकारी फिगर्ज देनी है तो सरकारी फिगर्ज दे अगर उस में गैर सरकारी जोड़ देंगे तो इससे कनफ्यूजन पैदा हो जाता है। इसकी तरफ आप ध्यान दें कि इसका क्या जवाब है। इस वक्तव्य में जहा 10 हजार रुपये का जिक्र किया गया है मगर हाऊसेज कोलेप्सेज के मुत्तालिक दो बातें नहीं कही गई है। मैं यह मानता हूं कि सब फिगर्ज नही आ सकती थी मगर अंदाजा तो कर सकते थे जिस तरह से 164 का अंदाजा लगाया गया है इसी तरह से यह अंदाजा भी लगाया जा सकता था कि कितने मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गये है और कितने मकानों को नुक्सान पहुंचा है। यह भी एलान आप कर देते कि फिलहाल उनके लिये क्या किया गया है आगे तो जो होगा वह तो होगा ही। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यशवंत सिन्हा जी ने फरमाया कि ऐसी अफातेमवामी के वक्त में लोग सड़कों पर आ जाते हैं उनके लिये न खाने के लिये कुछ होता है न पीने के लिए कुछ वन्दोबस्त होता है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस स्टेटमेंट में यह नहीं बताया गया कि उनके लिये कितने किचंस खोल दिये गये हैं जो लोगों को मुफ्त खाना खिलाते हों। अगर नहीं खोले गये हैं तो उसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। मैं आखिर में यह पूछना चाहता हूं कि बिहार के इलावा और रियासतों में भी वैस्ट बंगाल में तथा यू०पी० में भी नुक्सान हुआ है लेकिन उसका इस स्टेटमेंट में कोई जिक्र नहीं है। उसकी तरफ भी, दूसरी रियासतों में भी क्या हुआ है यह वजीर साहब हमें बतायें और उसके मुताल्लिक उन्होंने क्या किया है। लास्ट में जो अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि वजीर साहब वहां खुद तशरीफ ले गये थे, प्राइम मिनिस्टर खुद तशरीफ ले गये थे लोगो को ढाढस देने के लिये वह ठीक है लेकिन फिल्फौर कोई ऐलान एक दो दिन में होना चाहिए कि इतने करोड़ रुपये सेंट्रल से जो हमारा ड्राउट रिलीफ है या दूसरे रिलीफ हैं उसमें से देंगे ताकि लोगों को पता लग जाय कि 20-30 करोड़ रुपये गवर्नमेंट ने इयरमार्क किये है। बाद मे तफसीलात हो सकती है, बाद में उनको बताया जा सकता है मगर यह जो 30 लाख रुपये हैं इनसे कुछ नहीं होगा। बाकी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड की तरफ से टोकन होता है वह ठीक है मगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो असिस्टेंस होता है उसका ऐलान होना चाहिये। इसलिये इसके मुताल्लिक आप का क्या नजरिया है ?

†[شری غلام رسول مٹو (جموں و کشمیر): جناب وائس چیرمین- میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے اس ہاؤس کے ذریعے اس آفات سماوی پر ان لوگوں کو جو دکھ ہوا

[ ]† Transliteration in Arabic Script.

چیزوں کی انکو ضرورت ہے اور ان کے ہوتے ہوئے وہ چیزیں انکو جلدی پہنچ جاتی ہیں - تو یہ کہنا کہ پرائم منسٹر وہاں کیوں گئے تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہے (مداخلت)

اپ سبھا ادھیکش: یہ تو کسی نے نہیں کہا ہے -

شری غلام رسول متو: میں وائس چیرمین صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک دو باتیں ہوئی ہیں - جن سے زیادہ مشکل پیدا ہوئی ہے - آج صبح جو آل انڈیا ریڈیو سے خبروں میں کہا گیا ہے - اس کی طرف وزیر صاحب کا دھیان دلانا چاہتا ہوں - آج صبح کی بات ہے آل انڈیا ریڈیو نے کہا کہ ۱۶۴ آدمیوں کی موتیں ہوئی ہیں (یہ بھگوت جھا آزاد کہتے ہیں) - مگر غیر سرکاری اندازہ کے مطابق چار سو موتیں ہوئی ہیں - اب آل انڈیا ریڈیو جو ہے وہ ہمارا اپنا ہے - اگر آل انڈیا ریڈیو سے دوردرشن آ جاتے ہیں کہ آفیشل فیگرس ۱۶۴ ہیں اور ان آفیشل فیگرس ۴۴۰ ہیں تو لوگوں میں ہیجان پیدا ہو جانا لازمی ہے - تو میں گورنمنٹ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں - کہ کیا آپ سے اس مسئلے کو آل انڈیا ریڈیو اور ٹیلیویژن والوں سے اٹھایا ہے - اگر سرکاری فیگرس دینی ہے تو سرکاری ہے جو سے ہیں ہمدردی کا پیغام بھیجتا ہوں - اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ہاؤس کی طرف انکو ہمدردی کا پیغام بھیجا جائے -

اپ سبھا ادھیکش (شری ستیہ پرکاش رسالویہ): کل ہو چکا ہے -

شری غلام رسول متو: جناب عالی- عرض یہ ہے کہ آفات سماوی جو آتے ہیں وہ کسی آدمی کے بنائے ہوئے نہیں ہوتے ہیں خدا کی طرف سے آتے ہیں - دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن اس کے بعد جب یہ آفات سماوی آ جائے تو کیا کرتی ہے اور کیا اپنی ذمہ واری سنبھال لیتی ہے- اور اس ہاؤس کو اسی کی طرف دھیان دینا ہے - میرے خیال میں پرائم منسٹر نے یہ خبر پاتے ہی پونہ میں یہ اعلان کر دیا کہ میں سویرا کو وہاں جاؤں گا - سوال یہاں اٹھایا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر کے وہاں جانے سے کیا ہوگا - یہ ایسا ہی واقعہ ہے کہ کسی کے گھر میں اگر کوئی موت کا واقعہ ہوتا ہے تو سینکڑوں آدمی وہاں ان کو ڈھارس بندھانے کہلائے جاتے ہیں- اس طرح حکومت کے سربراہ کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہاں جاکر ان لوگوں کی ڈھارس بندھائے اور یہ بھی ایک طریقہ ہوتا کہ وہاں جاکر دیکھ لے کہ کن

میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہار کے علاوہ اور ریاستوں میں بھی ویسٹ بلکال میں اور یو - پی - میں بھی نقصان ہوا ہے - لیکن اس اسٹیٹمنٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے - اسکی طرف بھی دوسری ریاستوں میں بھی کیا ہوا ہے یہ وایر صاحب ہمیں بتائیں اور اسکے متعلق انہوں نے کیا کیا ہے- لاسٹ میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وزیر صاحب وہاں خود تشریف لے گئے تھے - پرائم منسٹر خود تشریف لے گئے لوگوں کو ڈھارس دینے کھڑے ہو تھیک ہے لیکن فی الفور کوئی اعلان ایک دو ہونا چاہئے کہ اتنے کروڑ روپئے سنٹر سے جو ہمارا فنڈ ہے یا دوسرے ریلیف ہیں - انمیں سے دینگے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ بیس تیس کروڑ روپئے گورنمنٹ نے ایر مارک کیئے ہیں - بعد میں تفصیلات ہو سکتی ہیں - بعد ان کو بتایا جا سکتا ہے مگر یہ جو تیس لاکھ روپئے دئے ہیں ان سے کچھ نہیں ہوگا - باقی پرائم منسٹر ریلیف فنڈ کی طرف سے تو کچھ ہوتا ہے وہ تھیک ہے مگر سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے جو امداد دینی ہوتی ہے اسکا اعلان ہونا چاہئے اسلئے اس کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے]

SHRI V. GOPALSAMY: Mr. Vice-Chairman, Sir, what has happened is a heart-breaking tragedy. Last Sunday

تھیکرس دیں اگر اس میں فیور سرکاری جوڑ دیں گے تو اس سے کنفیوژن (confusion) پیدا ہو جاتا ہے- اس کی طرف آپ دھیان دیں کہ اس کا کیا جواب ہے - اس وکتویہ میں جہاں ۱۰ ہزار روپئے کا ذکر کیا گیا ہے مگر ہاؤسیز کولیپسیز کے متعلق دو باتیں نہیں کہی گئیں ہیں - میں یہ مانتا ہوں کہ سب فیگرس نہیں آ سکتی تھیں - مگر اندازہ تو کر سکتے تھے جس طرح سے ۱۹۴۳ کا اندازہ لگایا گیا ہے اسی طرح سے یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا تھا کہ کتنے مکان مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں اور کتنے مکانوں کو نقصان پہنچا ہے - یہ بھی اعلان آپ کر دیتے کہ فی الحال اس کیلئے کیا کیا ہے آگے تو جو ہوگا سو تو ہوگا ہی- تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یشونت سنہا جی نے فرمایا کہ ایسی آفات سماوی کے وقت میں اوپر سرکس پر آ جاتے ہیں انکے لئے نہ کھانے کیلئے کچھ ہوتا ہے نہ پینے کیلئے کچھ بندوبست ہوتا ہے - اسلئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس اسٹیٹمنٹ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کے لئے کتنے کچن کھول دئے گئے ہیں جو لوگوں کو مفت کھانے کھلاتے ہوں - اگر نہیں کھولے گئے ہیں تو اسکی طرف بھی سرکار کو دھیان دینا چاہیئے - میں آخر

[Shri V. Gopalsamy]

was a tragic Sunday for those who were sleeping in the night. They had to witness only a dawn of death and destruction. Hundreds have died and thousands have been badly wounded. Many would have been immobilised due to the fall of the debris. Thousands have lost their home and heart. Here the Government comes up with a statement to reduce, to minimise, to under-play, the casualties. First we were given to understand that the death toll in India, in these areas, is more than 500 and the death toll in Nepal is 250. But later, Nepal has confirmed that the death toll is 450 there. But you are trying to minimise the casualty number. This Government is not responsible for this earthquake. Then for what reasons are you trying to suppress the truth? If you suppress the truth, the affected will not get the relief. The bereaved members of the families affected will not get the relief. The communication system has been totally destroyed. Then, how could you make your assessment? How could you make your estimate when the communicaton system is totally destroyed? The casualty number from the rural areas could not be communicated. Sir, when the tragedy took place 54 years ago in the same terrain. Therefore, the casualty number was about 11,000. It was in 1934. Now the State is densely populated. It is a poverty-stricken State with earthquake-prone buildings. Therefore, the casualty number definitely should be higher. For what reasons are you trying to suppress the real figure?

Sir, the tragedy occurred in the early hours on Sunday. But for 16 hours the relief operation did not reach the affected people when they were crying, according to the B.B.C. report broadcast yesterday night at 7.30 for 16 hours the relief operations did not reach the affected people and particularly, the police were very much lethargic in their attitude towards the affected people. Of course, our hon. Prime Minister has gone there. It is his duty. The Opposition leaders have gone there. Some of the Chief Ministers have gone there. But what was the initial reaction on Sunday? No relief operations reached them as it was expected. Sir, when dams are constructed, when reservoirs are constructed, there is a possibility of tilting the ecological balance. When a tremor occurred in Idukki in Kerala as also on the borders of the State of Tamil Nadu, some experts gave the opinion that it was due to the Periar Dam, those were the reservoir-induced tremors. When I put this question to the Minister, he could not understand the question. I would like to know whether this Government will hereafter try to make a study about the possibility of tremors or earthquake occurring due to inducements from the reservoirs and dams. Of course, precise prediction is very difficult. But in some countries they have made good researches to be able to make precise predicitions. That is why in Japan when they had a severe earthquake in 1985 the damage was very minimum. They have developed, innovated, new and modern scientific and technological methods of predicting likely tremors and have formulated codes...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): Please put your questions for clarification.

SHRI V. GOPALSAMY: I am putting my question. This is very relevant because in Japan they have made researches and studies and they are following certain codes. Therefore, I would like to know this. Some experts have opined that in future also in this terrain the danger is always there. Therefore, I would like to know whether the Central Government will make research to make a precise prediction possible. With this I conclude.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, at the outset I do appreciate very much the visit of the Prime Minister to the site of calamity, to the most affected site of calamity. But what I cannot appreciate is that in the face of such disaster a report not fact-oriented but Prime Minister-orient-

ed has been submitted. The House and the people at large would like to hear what the impact of this disastrous earthquake has been. As Mr. Matto has mentioned, even the extent of the earthquake tremor has not been fully included here. From press reports we know even Delhi had a tremor. The north-eastern part of the country extensively had tremors though mercifully without very serious damage. But when you make a report on the earthquake I wonder how tris can be omitted. And there is no report of a preliminary assessment of the damages. I remember on the day of the tremor Akashavani reported that at Monghyr 101 houses were destroyed. Doordarshan at night reported that 600 people were killed out of whom 250 were killed in Nepal. According to Doordarshan report which cannot be said to be inimical to Government, at least 350 people died in Bihar. But here no such assessment has been given. It starts with the visit of he Prime Minister and it practically ends with the visit of the Prime Minister. I have nothing personal against the youthful Prime Minister. But, if the Ministers, in their obeisance to the Prime Minister, prefer to ignore the task before them, namely, intimating the damage to the House, then it becomes a dereliction of duty. I would like to ask the Minister when he will be in a position to make a report on the extent of damages owing to this earthquake, particularly in Bihar. The earthquake of 1934 was referred to. Monghyr was the worst-affected place and the first President of the country, Dr. Rajendra Prasad, headed the all-party rescue and relief operations committee at that time. Without trying to derive any political advantage out of this disaster, if the Government performs its duties fully and properly, then perhaps the best relief could go to those in the affected areas. But, without doing that, if the Government makes this type of an attempt in such a situation, then it is a wrong thing.

There is another thing also. I do not know whether the report is correct or not. The Minister has said about a medical college hostel and about a *madarsa*. From the reports of the All India Radio as well as the Doordarshan, the building of an educational institution collapsed and eighteen students died. But the next day in the Press a more depedable report came out that a hostel collapsed and, as result, 18 or 20 students died. At 4-40 or 4-45 A.M. when the tremor occurred, no school, no madarsa, could have functioned. Therefore, I would like the Minister to check up whether this is a fact or not.,

Before I conclude, I would be failing in my duty if I do not register my feeling of shock that I had when I heard over the radio and the TV. that only a sum of Rs. 30 lakhs has been sanctioned by the Prime Minister for this great disaster. This amount *of Rs. 30 lakhs is a paltry amount these* days, considered in the background of the devastation that has taken place. It is not only less than adequate, but is also an insult to the injury becuse such a small sum for such a big disaster is inconceivable. To sanction nothing would have been better. I would request the Minister to assure the House that before this session is over, he will submit a detailed report on the loss on the damages to buildings, crops and irrigation projects, on the loss of life and on the relief measures taken so far, because this statement only gives a very inadequate picture of the relief measures. It only says that the Government has taken this or that step to do this or that thing. What relief was disbursed, no concrete idea has been given. It is not a question of donation from the Chief Minister's Relief Fund or any other. It is a question of pulling all the resources in order to provide succour to the affected people of this worst disaster in this form after Independence.

With these words, I conclude.

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह जो भूकम्प की घटना हुई है यह हम सदी की बहुत बड़ी और संभवतः सबसे दुखद घटना हुई है। मुझे लगता है कि सरकार इसको बहुत लापरवाही से ले रही है। माननीय मंत्री जी ने सदन में जो वक्तव्य पढ़ा है, वह बड़ा निराशाजनक है और सरकार की ओर से मृतकों तथा पीड़ितों के लिए जो सहायता की गयी है, जिसका कि उल्लेख इस वक्तव्य में है, वह और भी निराशाजनक है। माननीय, प्रधान मंत्रीजी

[श्री ईश दत्त यादव]

ने बड़ी कृपा की कि घटना की सूचना मिलने के बाद वे वहां पर गए और अपने साथ माननीय कृषि मंत्री जी तथा अन्य मंत्रियों को भी ले गए। लेकिन कल शाम को पटना में माननीय प्रधान मंत्रीजी ने जो प्रेस कांफ्रेंस की, जो अखबारों में छपी है उससे लगता है कि प्रधान मंत्रीजी के लिए यह घटना कोई बड़ी चीज नहीं है क्योंकि उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस में यह कहा कि जितना शोर था, वैसी घटना नहीं थी। मुझे दुख भी हुआ और निराशा भी हुई कि देश का प्रधान मंत्री जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है वह वहां कहते हैं कि जितना शोर था वैसी घटना नहीं थी।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के इस वक्तव्य में मृतकों के बारे में जो सूचना दी गयी है, मुझे लगता है कि वह वास्तविकता के अनुसार नहीं है क्योंकि पैरा 2 से ही यह स्पष्ट है कि केवल बिहार की कुछ जगहों पर जाकर ही प्रधान मंत्रीजी, माननीय कृषि मंत्रीजी और मंत्रिपरिषद् के अन्य मंत्रियों ने थोड़ा बहुत स्थिति का जायजा लिया है। मंत्रीजी के वक्तव्य में यह है कि बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम और त्रिपुरा में भी भूकम्प का असर पड़ा है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, कालीपोंग, कुर्सियोंग, कलकत्ता में भी झटके महसूस हुए हैं। परन्तु मृतकों की सूचना केवल बिहार से ही मिली है। मैं कोई कारण नहीं समझ पाता कि सरकार जो हर तरह से समर्थ है, सरकार के पास अनेक एजेन्सियां हैं, वह दूसरी जगहों कितने लोग मरे हैं, क्या आर्थिक सहायता दी गयी है, क्या मेडिकल एड दी गयी है, वह जानकारी एकत्रित न कर सके। लगता है कि सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। पटना गए, बिहार गए, कुछ अस्पताल देखा, कोई मदरसा देखा और वापस चले आए। वक्तव्य में जिन स्थानों का उल्लेख किया गया है, उन स्थानों पर क्या हुआ, कितने लोग मरे, इसके बारे में सरकार की ओर से जानकारी नहीं दी गयी है, जो कि निराशाजनक है।

माननीय मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य के पैराग्राफ 5 में कहा है कि मृतक परिवार को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 30 लाख तो यूं ही नगण्य है इतनी बड़ी दुर्घटना के लिए और प्रत्येक परिवार के लिए 10 हजार रुपया दिया गया है। तो मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि क्या प्रत्येक मृतक के हिसाब से 10 हजार रुपया दिया गया है या अगर एक परिवार में 10 आदमी मारे गए हैं तो दसियों को मिलाकर के 10 हजार रुपया दिया गया है, इसके बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है मंत्री जी के बयान में।

दूसरी चीज माननीय मंत्रीजी से मैं यह जानना चाहूंगा कि मंत्रीजी ने कहा है कि, पैरा 12 में कहा है कि यह सर्वविदित है कि ऐसे भूकम्प आने के बाद कुछ अन्य झटके भी आते हैं। यदि इस तरह की कोई संभावना है, तो फिर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो पाए, फिर धन जन की हानि न होने पाए, सरकार इस संबंध में क्या व्यवस्था कर रही है ताकि इस तरह के अगर झटके आएं तो उसके संबंध में व्यवस्था की जा सके और धन जन की हानि न हो सके।

तीसरे मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि पैराग्राफ 13 में इन्होंने कहा है कि प्रधान मंत्री के दौरे से जनसाधारण का मनबल बहुत ऊंचा हो गया है। इतनी बड़ी मुसीबत में लोग पड़े हुए हैं यदि आप 10 हजार की आर्थिक सहायता देते है—आपके अस्पतालों में दवाएं नहीं हैं, आपके पास मृतकों की सही जानकारी नहीं है और आप वक्तव्यों में कह देते हैं कि एकदम प्रधानमंत्री चले गए तो वहां पर पूरे पीड़ित लोगों का मनोबल ऊंचा हो गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपकी और प्रधानमंत्री जी की बड़ी कृपा रही, आप लोग गए कहां जहाज, हैलिकाप्टर और कार के अलावा किसी पीड़ित गांव में आप लोग पैदल चला भी किए, वहां के लोगों के कष्ट का अनुभव करने के लिए, पीड़ित लोगों की व्यथा सुनने के लिए कहीं गए भी आप कि मुख्य मंत्री और दूसरे लोगों ने हैलिपेड पर जो आंकड़े दे दिए उन्हीं आंकड़ों को लेकर के आप दिल्ली वापस चले गए। और

अंत में मैं अनुरोध करना चाहूंगा सरकार से, मान्यवर आपके माध्यम से, कि आर्थिक सहायता बहुत कम है, दवाओं की व्यवस्था बहुत कम है, कम से कम मृतक लोगों को एक-एक लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): उनके परिवार वालों को, उनके आश्रितों को, मृतकों को दिया नहीं जा सकता।

श्री ईश दत्त यादव : मृतक के आश्रितों को, परिवार वालों को एक-एक लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और दूसरी जो आशंका व्यक्त की है माननीय प्रमोद महाजन जी ने और माननीय यशवंत सिन्हा जी ने कि इस तरह से जो विपत्ति आती है उसमें सरकार की ओर से जो आर्थिक सहायता दी जाती है उसका अधिकारी लोग बड़ा गोलमाल करते है और पीड़ित तक यह सहायता नहीं पहुच पाती है। इसलिए इन दो माननीय सदस्यों की भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह एक सर्वदलीय समिति बनाए जो इसकी देख-रेख करे और उसकी देख-रेख में इस तरह की सहायता दी जाए।

मान्यवर, अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार इन घटना से जहां-जहां भी संकट उत्पन्न हुआ है, लोग मरे हैं, धन-जन की हानि हुई है, उसके संबंध में डिटेल मंगाकर के, रिपोर्ट मंगाकर के इस माननीय सदन में फिर वक्तव्य दे।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : श्रीमती प्रतिभा सिंह।

श्री रजनी रंजन साहू (बिहार) : मैंने सबसे पहले उन्हे नाम दिया था, मैं उस इलाके से आता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): अभी तक कोई महिला सदस्य नहीं बोली है श्रीमती प्रतिभा सिंह।

श्री रजनी रंजन साहू : मैंने पहले नाम दिया था।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) अच्छा देखते है, श्रीमती प्रतिभा सिंह का नाम पुकार लिया है।

श्री रजनी रंजन साहू आपके सामने नाम है तब भी आप नाम नहीं बोलते है। हम बैठे हुए हैं फिर भी आप नाम नहीं बोलते हैं, तो यह तो बड़ी दुखद बात है।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (बिहार) : महोदय, मैंने 1934 का भूकंप देखा है। मैं तब बहुत छोटी थी। लेकिन मैंने देखा है कि वह इतना बड़ा भूकंप था जिसका कोई हिसाब नहीं। 27 लाश एक ही मकान से निकली थी। वह मकान हमारे मकान के सामने था। तो सबसे पहले तो मैं प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करूंगी कि वह तुरन्त गये। उनके वहां जाने से बहुत फायदा हुआ है। बिहार के रहने वालों को पता है कि कितना फायदा होता है क्योंकि सारी मशीनरी गियर अप हो जाती है। दरभंगा, मुंगेर और मधुबनी में वे गए और तुरन्त 10 हजार रुपयों एक परिवार के लिए की व्यवस्था की। इसके ये माने नहीं है कि ये दस हजार दवाई के लिए भी हो गए। मकान की मरम्मत के लिए भी हो गये, यह तो तात्कालिक सहायता है। तो जो कुछ अच्छा काम हो उसकी ख्वामख्वाह बुराई करने से कोई फायदा नहीं होता। जो दैवी प्रकोप होता है वह राजनीतिक नहीं होता है, न उसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहिए। मान लीजिए जनता सरकार में कोई दैवी विपत्ति आ जाती और प्रधान मंत्री उस समय के वहां जाते तो उसमें कोई बुराई नहीं। मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार प्रधान मंत्री जब वहां गए तो उससे लोगों को जानकारी हुई है और वहां जाकर उन्होंने सारी मशीनरी को गियर अप किया।

श्रीमन्, आप जानते हैं कि बिहार अर्थक्वेक जोन में है। हम लोगों ने 1934 का भूकंप देखा जब मुजफ्फरपुर में तबाही हुई थी। एक कमरे में हम लोग थे और हमारी आंखों के सामने उसमें से नदी निकलने लगी। इस प्रकार हमारा अनुभव

[श्रीमति प्रतिभा सिंह]

है। मेरे पिताजी, श्री सी.पी.एन. सिंहजी उस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन थे। बहुत काम रिलीफ का किया था। वहां उस समय सारी शुगरकेन की फसल खराब हो गई मिलों में पानी भर गया था। किसान बरबाद हो गये थे। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार के सामने दो तीन सवाल रखना चाहती हूं।

एक तो बिहार खास अर्थक्वेक जोन में है। बिहार, असम और पश्चिमी बंगाल में से बिहार और असम खास क्षेत्र हैं। इन दो जगहों में ऐसे सेंटर खुलने चाहिए जिससे भूकंप आने की सूचना उनको मिल सके और जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है इसके ऊपर भी रिसर्च हुई है, जानकारी हासिल की जा सकती है वैज्ञानिकों से। क्योंकि जब भूकंप आते हैं तो जमीन के अंदर कुछ परिस्थितियां बदलती हैं जो भूकंप का संकेत देती हैं।

दूसरी बात जो मैं सरकार से कहना चाहती हूं वह यह है कि भूकंप आने पर अपनी रक्षा कैसे की जाए, इसके विषय में कोई न कोई पाम्फलेट मास मीडिया के द्वारा आप प्रचारित करें क्योंकि जैसे ही भूकंप आता है तो लोगों के मकान हिलने लगते हैं तो उनको जानकारी हो जाए कि वे मैदान में हैं तो कहां रहें, घर में हैं तो कहां जाएं क्योंकि चौखट के नीचे होंगे तो बच सकते हैं, लेकिन अगर उन पर दीवार गिर गई तो वे दबकर मर जाएंगे। तो ये सब जानकारी लोगों में कराएं ताकि लोग अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर सकें।

तीसरी चीज यह है कि नदी की धारा अक्सर बदल जाती है। तो बिहार में ऐसी कोई सूचना है कि कोसी, गंडक आदि, नदियों की धारा बदली है या नहीं। कल मार्ग्रेट आल्वा जी ने अलग अलग संस्थाओं की जो महिला सदस्या हैं उन सब से मीटिंग की थी कि किस तरह से हम बिहार में जाकर जो वहां दवाएं बांटेंगे, राशन बांटेंगे या जो कुछ भी बांटेंगे उसकी देखभाल करें। यहां हम लोगों ने एक अपील दायर की है, अखबारों में छपवाई है कि जो लोग दवा, पैसा कपड़ा जो कुछ भी दे सकते हैं वह दें ताकि उनके बीच में जाकर बांटा जा सके।

यह जो कहा गया कि इसमें ऐसा क्यों लिखा गया कि लोगों का मनोबल ऊंचा हुआ तो मैं बताना चाहती हूं कि लोगों के अंदर मनोबल बढ़ा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : इसका उत्तर मंत्री जी दे देंगे आप अपना स्पष्टीकरण पूछें।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : मैं वहां की नागरिक हूं इसलिए कह रही हूं कि मेरा मनोबल बढ़ा है। ऐसे ही बहुत लोगों का मनोबल बढ़ा है प्रधान मंत्री जी के जाने से।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं भी वहां का रहने वाला हूं।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : यह मुझे मालूम है। मैं आपको जानती हूं, आपको पहचानती हूं। मैं यह भी कह सकती हूं कि उम्र में आप मेरे से छोटे हैं इसलिए 34 का अर्थक्वेक नहीं देखा है।

श्री यशवंत सिन्हा : मैंने देखा है। उस दिन मैं वहीं था।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : यह 1934 के बारे में कह रही हैं।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : : मैं यह कह रही हूं कि लोगों का मनोबल जरूर ऊंचा हुआ है। जो लोग वहां गये हैं, जो लोग इसमें मदद कर रहे हैं उन सब को बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रधान मंत्री जी वहां गये हैं उनके वहां जाने से वहां के लोगों का मनोबल ऊंचा हुआ है। जो वहां ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, मुंगेर जिले के लोग हैं, दरभंगा के लोग हैं, मधुबनी के लोग हैं हम लोगों के रिश्तेदार वहां पर हैं, मैं वहां पर पैदा हुई हूं, बड़ी हुई हूं, उसी बिहार की मेरी राजनीति है इसलिए मैं जानती हूं कि वहां का मनोबल बढ़ा है।

इस पर आक्षेप करने से कोई लाभ नहीं है। अगर कोई अच्छी बात होती है उस पर आक्षेप नहीं करना चाहिए। जो लोग दुखी हैं, जिनके घर के लोग मारे गये हैं व जिनके मकान गिर गये हैं या जो सड़क पर हैं उनको किस तरह से मदद कर सकते हैं यह हमें आज देखना है। जो दो-तीन सवाल मैंने रखे हैं मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मंत्री महोदय उन पर ध्यान दें और उसके लिए भी कार्रवाई करें जहां दूसरे प्रदेशों में भी अर्थक्वेक आया है, उनके यहां भी क्षति हुई है, वहां भी रिलीफ वर्क की व्यवस्था होनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)। श्री रजनी रंजन साहू।

श्री राम चन्द्र विकल: (उत्तर प्रदेश): मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने इसी विषय पर स्पेशल मेंशन दिया था। उपसभापति महोदय ने कल इस को मंजूर नहीं किया, पेंडिंग रखा और आज यह कहा कि जब स्टेटमेंट होगी तब आप बोल लीजियेगा। यह उनका आश्वासन था मुझे आज बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): स्पेशल मेंशन की लिस्ट में आपका नाम नहीं था।

श्री राम चन्द्र विकल: उन्होंने मना कर दिया था। यह कहा था कि इस पर जब बहस होगी तो आप हिस्सा ले लेना।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): उपसभापति महोदय, दिनांक 21 अगस्त, 1988 को लगभग 4.39 बजे बिहार के अधिकतर हिस्सों में भयंकर भूकम्प के झटकों से जो जान-माल का नुकसान हुआ। इस भूकम्प की तबाही से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इस भूकम्प से प्रभावित नागरिकों के प्रति मैं अपनी हार्दिक सम्वेदना व्यक्त करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) पारा मदन कर चुका है। आप स्पष्टीकरण पढ़िये।

श्री रजनी रंजन साहू: मैं वहीं आ रहा हूं। आपने मेरा नाम शुरू में न पुकार कर अंत में पुकारा तो सही, इसके लिए आपको धन्यवाद। साथ ही मैं प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की तत्परता एवं समय पर बिहार के दौरे की सराहना करता हूं और उन्हें हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिहार के लोगों में इस आपात्कालीन एवं दखद घड़ी में वह वहां गये। इससे लोगों में आत्म विश्वास पैदा हुआ है। माननीय सदस्य यशवंत सिन्हा जी से मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री किसी एक पार्टी के नहीं होते वह देश के प्रधान मंत्री होते हैं और यह स्वाभाविक है कि जब देश का प्रधान मंत्री किसी आपत्तकाल में कहीं जाता है तो वहां के लोगों में आत्म विश्वास जगत है। विभिन्न अखबारों में अलग अलग रिपोर्ट छपी है। भूकम्प से सबसे बड़ा असर दरभंगा जिले में पड़ा है। वहां 200 लोगों के मरने की खबर है और छत गिरने से एक स्कूल के 17 बच्चों के दबने की खबर है। मधुबनी में सरकारी तौर पर 51 लोगों के मरने की खबर है। समस्तीपुर में लगभग 21 लोगों की मरने की खबर है। वहां पर बूढ़ी गंडक के पुल का एक पाया धंस जाने से रेल यातायात दरभंगा और समस्तीपुर के बीच बंद हो गया है। इसी तरह से विभिन्न जिलों में, बेगूसराय में 6, सहरसा में 11 और फारबिसगंज में 2 लोगों के मरने की खबर है। ये सब अखबारों की खबरें हैं। क्या सरकार को इतना पता है? जो आंकड़े मंत्री महोदय ने दिये हैं वे आंकड़े सही हैं या जो आंकड़े अखबारों में निकले हैं वे सही हैं, इस पर मंत्री महोदय प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। मुजफ्फरपुर में भूकम्प के झटकों से कच्चे मकान गिर गये हैं और पक्के और बड़े मकानों में दरारें पड़ गई हैं। मैं सर्वप्रथम यह जानना चाहूंगा कि कहां मरने वालों की संख्या है और उनमें गांवों में मरने वाले कितने हैं और उनमें से कितने हरिजन हैं क्योंकि ऐसी आपदा के समय गरीबों और हरिजनों का ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए उनके लिए क्या कोई विशेष सहायता का प्रबंध किया गया है या नहीं? दूसरी बात मैं यह

[श्री रजनी रंजन साहू]

चहता चाहता हूं कि मैं मुजफ्फरपुर से आता हूं और यह जानता हूं कि पूरा नार्थ बिहार सिस्मिक जोन में आता है। वहां पर इस तरह के भकम्प की आशंका बनी रहती है और इस तरह के सिस्मिक जोन के संबंध में फोरकास्ट की घोषणा वैज्ञानिक कर चुके है। इसलिये क्या सरकार इस संबंध में फ रकास्ट की स्थायी व्यवस्था करेगी और वहां पर कोई कंट्रोल रूम बनाएगी जिससे फोक रास्ट किया जाय ताकि लोग सचेष्ट हो जाय? यह बात रही है कि इसका सही समय नहीं बताया जा सकता है, लेकिन एक दिन आगे-पीछे कुछ तो पता लग सकता है इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो सिस्मिक जोन है उसमें इस तरह के कंट्रोल रूम की व्यवस्था सरकार ने की है या नहीं? तीसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि स्टेटमेंट में कहा गया है कि 8 डाक्टरों की टीम चिकित्सा के लिए भेज दी गई है, लेकिन यह दुखद बात है क्योंकि वहां पर जितने डाक्टरों की आवश्यकता है उसमें आठ डाक्टर कोई स्थान नहीं रखते हैं। यह भी कहा गया है कि मुंगेर में दवाइयों की कमी है। मैं जानता हूं, सभी जगहों में और सभी अस्पतालों में दवाइयों एवं डाक्टरों की कमी है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन अस्पतालों में दवाइयो की कमी है या डाक्टरों की कमी है वहां पर डाक्टरों की स्पेशल टीम भिजवाएंगे? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जो बच्चे एक मदरसे में 4.49 भकम्प आने पर दबकर मर गये और जिनकी संख्या 17 बताई जाती है, वे वहां पर होस्टल में रहते थे या उसमें रहने के लिए गये थे, इस पर भी मंत्री महोदय विशेष तौर पर प्रकाश डालें और अपना स्पष्टीकरण दें।

श्री राम नरेश यादव : (उत्तर प्रदेश) माननीय सभापति, बीसवीं सदी की यह अप्रतिम घटना रही है और इस घटना को कल सदन ने बहुत गंभीरता के साथ लिया था और यही कारण था कि सदन ने अपनी शोक संवेदना भी व्यक्त की, उनके प्रति अपनी सहानभूति भी व्यक्त की। लेकिन ऐसा लगता है कि यह सरकार उसे भगवान के भरोसे पर चल रही है वैसे ही इस आपदा से पीड़ित, जो यह प्राकृतिक आपत्ति आई है उसके चलते वहां के लोगों को भी उसी तरह से मरने के लिए छोड़ दिया गया है। इस बयान से स्पष्ट लगता है और यह बात सही है कि इस सूचना के मिलते ही प्रधानमंत्री अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे। लेकिन इसके साथ-साथ एक बात जो बहुत ही सोचने की है वह यह है कि इस वक्तव्य के बाद यह लगता है कि केवल प्रधानमंत्री और उनके साथ मंत्री लोग वहां गये, इसके अलावा उन आपत्ति पीडित लोगों के बारे में सरकार की कोई ठोस योजना, उनको राहत पहुंचाने के लिए कोई ठोस सुझाव या कोई ठोस कदम का संकेत तक नहीं दिया गया है। इस वक्तव्य में जो कुछ है वैसा बयान समाचार पत्रों में भी आ चुका 3.00 P.M. है। करीब 1500 लोग मर गये। इससे भी ऊपर यह भी कहा गया 1934 में जो भकम्प आया था उससे कहीं बड़ा यह भूकम्प था, कम नहीं था. लेकिन सरकार ने कौन सी ऐसी बात हो गई थी कि सरकार ने सारी समस्या को और जो भयंकरता है उसको कम से कम आंकने का काम किया है। इसका उत्तर भी मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं। साथ ही साथ एक बात और भी है। मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री जी इस बात को सोच रहे थे जैसे यह भूकम्प बिहार और बंगाल में आया है सारे लोग तबाह हो रहे हैं वैसे मंत्री जी को यह आशंका थी कि उनके इस वक्तव्य को पढ़ने के बाद लोगों के मन में निराशा आएगी और एक दूसरे प्रकार का भूकम्प उठेगा और इस भकम्प से वहां के लोग और परेशान होंगे इसलिए इन्होंने एक वाक्य यह भी कह दिया कि इस बारे में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है; लगता है कि सरकार ने सारे कदम उन लोगों के लिये उठाये हैं। मैं कहना चाहता

हूं कि अस्पताल में दवा की कमी पाई गई। अभी दिल्ली में यहां पर राष्ट्रपति भी रहते है, प्रधानमंत्री भी रहते हैं और यहां संसद् सदस्य भी रहते हैं लकिन यहां पर जब अस्पतालों में दवा के अभाव में और फिर ग्लूकोज भी जो चढ़ाया जाता है गड़बड़ वाला दूषित रहता है उसके कारण लेडी डाक्टर भी मर जाती है उसकी भी जिन्दगी की रक्षा यह सरकार नहीं कर पाती तो वहां पर निरीह जो गांव में झोंपड़ियों में रहने वाले हैं जिनके मकान गिर गये हैं देखने वाला कोई नहीं है विशेष रूप से प्रभावित तो वह तबका होता है जो गांव का गरीब इंसान है। आपके बयान में आया है कि हम लोग वहां पर थे तो कुछ लोगों न गांवों से जो आ गये थे उन लोगों से हमने जानकारी ली। मुझे तो प्रसन्नता होती कि हमारे कृषि मंत्री जो अपने आप को गांव से आने वाली बता ते हैं अगर कहीं दो गांवों में जा कर उन गांवों के लोगों से बात करके उन से विचार-विमर्श करते उनके संकट को देखते तो बात समझ में आती कि सचमुच में कहीं पर इनके मन में गांव वाले जो इस तरह से पीड़ित लोग हैं उनके प्रति सहानुभूति के स्वर जग रहे है, उमड़ रहे हैं, तब तो बात दिखाई पड़ती लेकिन ऐसा किया भी नहीं गया। सचमुच में पहली व्यवस्था करनी पडेगी कि जितने गांवों के लोगों के मकान गिर गये हैं रहने का ठिकाना नहीं है दवा की व्यवस्था नहीं है उधर आपका ध्यान विशेष रूप से जाना चाहिये। आपने यह भी अपने बयान में कह दिया कि आश्वासन भी मिल गया है कि खाद्यान्न की और दूसरी चीजों की कोई कमी नहीं है। कमी है, लेकिन आप नहीं करना चाहते हैं इसलिए उनके लिए जिनके मकान गिर गये हैं, कोई रहने के लिए ठिकाना नहीं है, मवेशी मर गये हैं उनको मुफ्त खाने की व्यवस्था आपको करनी चाहिये। यह भी सदन को आश्वस्त करना चाहिये, कि सचमुच में इस संबंध में आपने क्या योजना बनाई है? जिनके मवेशी मर गये, मनुष्यों के बारे में आपने बताया है कि कितने मरे हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि कई हजार लोग मरे हैं और जब कई हजार लोग मरे है तो अपने अधिकारियों के जरिये से जो वक्तव्य आया है यह तो रद्दी की टोकरी में फेंकने के लायक है। उन पर विश्वास न करें आप वृहद रूप से सर्वे कराएं कि कितने लोग मरे हैं कितने मवेशी मरे हैं क्योंकि किसान की रीढ़ जहा पर उसका श्रम है वहां पर मवेशी भी हैं। मवेशियों के बारे में कोई चर्चा नहीं है इसलिए उसका भी सर्वे कराए और उनके लिए क्या व्यवस्था आप करने जा रहे हैं उनके मवशी मर गये बचारों की जिन्दगी का सहारा चला गया और आप उनको लिए 10 हजार रुपये की व्यवस्था कर रहे हैं इसलिए यह तो बिलकुल अन्याय है। ऐसे मामले में कम से कम एक लाख रुपये देने की आप व्यवस्था करे। जो मवेशी मरे हैं मवेशी खरीदने के लिए कुछ विशष आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था करें। मुफ्त दवाएं बांटने की व्यवस्था करें। जो विस्थापित हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था आप करें। इसके बारे में कोई चर्चा आपक बयान में नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि आप इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट मंगाए और मंगवा कर सदन को आने वाले दिनों में आश्वस्त करें कि सचमुच जो वहा के पीड़ित लोग हैं उन लोगों की जिन्दगी के साथ आप खिलवाड़ नहीं होने देंने। नहीं आप खिलवाड ही करने जा रहे हैं उनकी जिन्दगी के साथ।

श्री राम चन्द्र विकल: उपसभाध्यक्ष महोदय, यह वक्तव्य जो कृषि मंत्री जी न दिया है, प्रधानमंत्री जी मौके पर गये अपनी मंत्री-परिषद् के कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और आवास मंत्री को लेकर उसके लिए स्वागत और बधाई है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं। सारा सदन उसका ऋणी है। मैं कृषि मंत्री जी से जो उन्होंने मृतकों की संख्या बताई है जिसमें संदेह प्रकट किया है कि बढ़ सकती है मैं यह जानना चाहता हूं कि मरने वालों की संख्या के इलावा मरने वाले मवेशियों की संख्या तथा फसल के बारे में कोई चर्चा नहीं है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसे ही सरकार को इन चीजों के बारे में मालूम हो क्योंकि आज

[श्री राम चन्द्र विकल]

तो विज्ञान का युग है और सरकार के पास साधन भी हैं। जैसी ही सरकार को मालूम होता रहे वह सदन को अवगत कराते रहेंगे या नहीं कराते रहेंगे, चाहे वह आसाम की हो, चूंकि आसाम की कोई खबर नहीं है, बंगाल में ऐसी कोई दुर्घटना की खबर नहीं है। सिक्किम से भी। बिहार, सिक्किम जहां-जहां ये भूकम्प की दुर्घनाएं हुई हैं उसकी तात्कालिक सूचना सदन को देने की कृपा करते रहेंगे। दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि यह राजनैतिक प्रश्न नहीं है। अगर माननीय सदस्य कुछ इसका बुरा न मानें तो संसद की सहमति बनाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए और वह बना देनी चाहिये। तीसरा, सभी राज्य सरकारों से और समाजसेवी संगठनों से अपील करके सरकार को सहयोग लेना चाहिये और इसकी देखभाल जरूरी है कि वह सही पहुंच। चौथा, चीन के वैज्ञानिकों की लोगों न चर्चा की। उपसभाध्यक्ष महोदय, जापान में सबसे ज्यादा भूकम्प आते हैं और जापान के भूकम्पों की दर्दनाक कहानियां चौधरी तेज सिंह उस समय के कवि भजनों से सुनाया करते थे। दिल को दहला देने वाली बातें थीं। उन दिनों हमारा कोई इतना नहीं था लेकिन जापान की दुर्घटनाएं यहां के कवि गाकर सुनाते थे तो जल्दी मालूम हो जाता था। मैं स्वयं जपान गया हूं। ज्वालामुखी पहाड़ सबसे ज्यादा फटते हैं। उन पहाड़ों के ऊपर से, जिसमें गंधक जलती थी, रोपवे से हम लोगों को जापान के लोगों ने गुजरा। वहां जापान के लोगों ने जंगल के अन्दर वेधशाला बनाई है। मैं विश्वास के साथ सन 1970 की घटना बताता हूं। जापान के लोगों ने विश्वास के साथ यह कहा कि भूकम्प हमारे यहां आया करते थे हमने उनको पूरा कंट्रोल कर लिया है। अब जापान में भूकम्प नहीं आते हैं जहां सबसे ज्यादा भूकम्प आते थे, ज्वाला मुखी पहाड़ फटते थे। वैसे वीभत्व काण्ड हमारे देश में नहीं होने चाहिए। जापान की तरह से हमें भी कंट्रोल करना चाहिये। वहां के वैज्ञानिकों का जो शोध है उसका फायदा गवर्नमेंट उठाना चाहेगी या नहीं। जहां सबसे ज्यादा भूकम्प आते थे वहां उन्होंने उस पर कंट्रोल कर लिया, यह मैं खुद देखा है। दिल्ली में भी झटके बताये गये हैं। अतः इस सारे मामले को देश के स्तर पर लें कि किस तरह से आइंदा भूकम्प जल्दी से जल्दी रोके जाये। इस मामले में अपने वैज्ञानिकों या विदेशी वैज्ञानिकों की सलाह से तुरन्त कोई कमेटी बनाने का विचार करना चाहिए। पांचवां मैं जानना चाहता हूं कि नेपाल में घटना हुई हो या बंगलादेश में, गुटनिरपेक्ष देशों में होने की वजह से भारत की भूमिका नेपाल और बंगलादेश की इन दुखद घटनाओं में सहायता करने की है या नहीं। इन्हीं चन्द लफ्जों के साथ मैं मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी का आभार मानता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): Shri Ram Jethmalani. Kindly be brief.

SHRI RAM JETHMALANI (Karnataka): Very brief, Sir. While we must concede that the present state of our geological and scientific knowledge is not such as to prevent such ghastly tragedies altogether, at least we can be in a state of preparedness and we can always keep some amount of vigilance and care, particularly the facility of communication.

Sir, the first thing which calls for comment, and it is a very serious comment, is that at 7-30 in the morning of Sunday the news bulletin of the All India Radio almost gave an impression that nothing had happened in India and that somethig had happened in areas adjoining Bihar, and no damage was reported up to 7-30. This is the state of preparedness. Geologists have at least warned that these are the areas which are susceptible to this kind of tragedy, and, therefore, we expect of our Government at least to keep our communication in order. This is one point which requires a serious answer.

Second, it is said that there is no information about damage to major irrigation projects. Newspapers have reported that irrigation bandhs which constitute the banks of rivers and prevent flooding, have been

seriously damaged. I would like the hon. Minister to check up this and give us a very authentic account of whether or not this damage has taken place.

Then, Sir, in the third paragraph there is a reference to the Prime Minister having talked to a large number of people including those who had come into the towns from the rural areas. These person who had gone from the rural areas to the towns or the cities where the Prime Minister went, obviously did not go for *darshan* of the Prime Minister. They have escaped from damage and there were attempts made to dilute that damage. Obviously they must have found their conditions so intolerable that they have gone in search of assistance and support to these urban areas. Now, we want to know why is it that the Minister of Agriculture himself did not divide forces. Why should they all congregate at one place? I understand the Prime Minister going to the urban areas and tre Agriculture Minister should have gone to the rural areas and found out what was happening there. He should tell us what exactly is meant from this trat these people have come from rural areas. Why have they come? What have you done to prevent them from coming? What have you done to make it possible for them to go back to the areas from where they have come?

Then on the second page of the document, the Prime Minister has expressed a hope that to tackle the situation voluntary agencies and the people will themselves come forward. We are willing to come forward, but will the hon. Minister concretely tell us what is it that he expects private citizens to do, what is it that he expect the voluntary organisation to do so that we should go about and mobilise national resources and the resources of private persons and such voluntary organisations. I want to have light on what kind of help is required by the Gove-nment from these organisations and private individuals.

Then there is an admission in this document of shortage of medicines. I particularly want to know what kind of medicines are in shortage, what kind of medicines you are not able to immediately secure and whether you require any foreign assistance in the matter of procuring the necessary kind of drugs which you require. Please tell us so that if you cannot do it, we might at least endeavour to do it for you and we might render to you such assistance that you want.

Lastly while the Prime Minister ought to be where he is, and he deserves to be congratulated for his presence on the site of tragedy and I am sure the presence of the Prime Minister must have been a type of healing touch to some people at least, what I do not like is that people who think that the Prime Minister's presence brings them some feeling of security and they feel fortified. They don't make declarations of that kind, which the Minister of Agriculture heard and which he geefully reports to the House. On the other hand I do not share my colleague, Mr. Sinha's anger. After all, some amount of obscene vulgarity is natural because that is the condition on which the hon. Agriculture Minister holds his office.

श्री भजन लाल : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने हाऊस में बहुत ही रुचि और कुछ सदस्यों ने समवेदना भी प्रकट की, बहुत दुख जाहिर किया। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में पहले कहा था, हम सबको और सारे राष्ट्र को इसमें गम्भीर चिंता है। लेकिन आप जानते हैं, उपसभाध्यक्ष जी, कि यह कोई सरकार की गलती से नहीं—चाहे वह प्रदेश की सरकार हो, चाहे वह सेंटर की हो, यह आप जानते हैं कि यह नेचुरल केलेमिटी है और यह बात ईश्वर के अधीन है। बहुत सी दफा ऐसे भूकम्प आते रहे हैं और अकेले हिन्दुस्तान ही नहीं, सारी दुनिया में जैसा कि विकल साहब ने कहा है जापान में सदा भूकम्प आते हैं, अब जरा कम हुए हैं। उसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा, सबसे पहले बोलते हुए सुकोमल सेन जी ने कहा कि सम चार-पत्रों में ज्यादा मौतें बताई गई और आपने इस बात को छिपाया है और ठीक सूचना नहीं दी है।

[श्री भजन लाल]

उपसभाध्यक्ष जी, इसमें छिपाने की कोई बात ही नहीं है । कई सदस्यों ने यह संशय जाहिर किया है । लेकिन छिपाने की बात तो तब हो जब सरकार के हाथ से कोई गलती हो जाए, या प्रदेश सरकार के हाथ से गलती हो जाए । जैसा कि मैंने पहले कहा, यह कुदरत की देन है, इसमें छिपाने की तो कोई बात ही नहीं है, बल्कि प्रांतीय सरकार इसे कैसे छिपायेगी । प्रांतीय सरकार तो भारत सरकार से जब कोई सहायता मांगती है, तो ज्यादा बताकर सहायता मांगती है । अगर वह थोड़ा बतायेंगे तो उनको सहायता कम मिलेगी । नुकसान तो उनका है । इसलिए बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है । इसलिए आप गहराई में जाइये । इसमें छिपाव की कोई बात नहीं थी । जैसा आपने कहा और कुछ आशंका जाहिर की कुछ और भी हो सकता है । हाउस में जो बात कही जाए वह जितने प्रमाणित आंकड़े हैं हमारे पास उनके मुताबिक ही हमने कहा है । लेकिन ऐसी बात नहीं कि इसमें कुछ छिपाया गया हो । ऐसा इसमें नहीं है कि कोई 40, 50 या सौ, दो सौ का फर्क होगा, हां ऐसा हो सकता है कि इसमें एक-दो या चार पांच का फर्क हो सकता है और वह भी इसलिए कि किसी जगह पर कोई सीरियस जख्मी हो गया होगा जिसकी कि डैथ होने की संभावना हो सकती हो या एक आध आंकड़े मिलने में कमी भी कारण हो सकती है । इसलिए हमने कहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा अन्तर हो । हमने आपके सामने स्पष्ट किया है सब कुछ लेकिन कुछ और भी मौतें हो सकती हैं । दूसरा सुकोमल जी ने कहा कि घरों के बारे में जानकारी नहीं दी और घायलों के बारे में भी नहीं बताया । घायलो के बारे में तो अभी मैंने आपके सामने रखा है कि 1209 आदमी जख्मी हैं । प्रधान मंत्री जी तीन अस्पतालों में गए और जा करके मरीजों से उन्होंने बात-चीत की और उनसे पूरी तसल्ली उन्होंने की और एक-एक मरीज से बात की कि कितने आपके घर में लोग थे और कितने जख्मी हुए तथा कौन मरा है और क्या हालत है । प्रधान मंत्री जी ने पूरी सहानुभूति लोगों के साथ दिखाई । वहां के मुख्य मंत्री जी भी उनके साथ थे । बहुत देरी की बात करना कि इनको पता नहीं लगा, कुछ किया नहीं और जब से होगा ऐसी बात नहीं है । आप जानते हैं परसों सुबह 4 बजकर 39 मिनट पर भूकम्प आया और वहां की प्रांतीय सरकार फौरन मौके पर पहुंच गई । सभी जगह भाग-दौड़ की । हवाई जहाज से भी, सड़क से जा सकते थे तो सड़क से गए मंत्रिमंडल के साथ और सारे अधिकारियों को भेजा । प्रधान मंत्री जी को ज्यों ही पता चला उन्होंने फौरन सारे डिपार्टमेंट को सचेत किया चाहे एग्रीकल्चर का महकमा है, चाहे डिफेंस की मदद लेने की बात थी, चाहे डाक्टरों के सहायता लेने की बात थी जिन-जिन डिपार्टमेंट का ताल्लुक था उन सभी को सचेत किया गया । इतवार को छुट्टी का दिन होते हुए भी सारे के सारे आफिस खोलकर सारे इसी काम में लग गए और सारा संपर्क स्थापित किया ताकि जहां कहीं भी नुकसान हुआ है या जहां कहीं भी ऐसी घटना घटी है वहां पर उन लोगों की पूरी सहायता और मदद की जाए । इसके अलावा आपने एक बात सही कही कि मैक्सिकों में एक भूकम्प आया था और ऐसा कोई इंतजाम होना चाहिए कि भूकम्प आने की पहले सूचना मिल जाए तो यह बड़ा मुश्किल है । हमने बहुत पता किया इस बारे में कि क्या भूकम्प की जानकारी पहले ही मिल सकती है लेकिन इसकी संभावना कम है, यह बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ पता लग सके और यह बहुत अच्छी बात भी है । जहां तक इसके बचाव का ताल्लुक है, आप जानते हैं जब भूकंप आता है तो कुछ सैकण्डज में ही सब कुछ हो जाता है और उससे निकलना बहुत कठिन हो जाता है । कोई आदमी भागकर निकल जाए एक-आध सैकंड में तो यह और बात है लेकिन सोए हुए या बैठे हुए आदमी को पता लगते-लगते ही सब कुछ हो जाता है ।

जहां तक गुप्ता जी ने कहा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भूकम्प ज्यादा आते हैं । कोई रेलवे ट्रैक को हानि हुई या नहीं और संचार माध्यमों में क्या पोजीशन है । संचार माध्यमों में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कहीं

कोई पोल भले ही टूटा हुआ हो सकता है और वह फ्लड की वजह से भी हो सकता है। लेकिन संचार में ऐसा कोई बिखराव या अव्यवस्था नहीं है जिसके बारे में कि पता नहीं चला हो। सब फौरी तौर पर पता लगा कि ऐसा नहीं हुआ। रेलवे में भी ऐसा नहीं हुआ कि जिससे यातायात ठप्प हो गया हो। एक जगह थोड़ा क्रैक आया है वह पता नहीं फ्लड की वजह से आया है या भूकम्प की वजह से आया है। फ्लड भी थोड़ा उस एरिया में है इसलिए हो सकता है कि पानी की वजह से आया हो लेकिन उससे ट्रैफिक रुका नहीं है, आहिस्ता-आहिस्ता स्लो करके रेल को वहां से पार किया जाता है।

इसी तरह से प्रमोद महाजन जी ने आशंका व्यक्त की कि पहले ज्यादा बनी थी और अब उतनी क्यों नहीं है तथा अखबार में कुछ ज्यादा आया और आने कुछ कम बता दिया। उनके बारे में मैंने आपको सब बताया है और उसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। छुपाएं तब जब इससे कोई लाभ होगा हो? हमदर्दी जितनी आपको है उससे भी ज्यादा हम को है। सारे देश को इस में हमदर्दी है। हो सकता है आंकड़ों में न जाकर ऐसी बात कहो हो क्योंकि अंदाज की बात है। लेकिन तीन दिन के बाद यह थोड़े ही हो सकता है। वहां के एम. एल.ए., एम.पी. जोकि जनता के नुमाइंदे हैं, वे प्रधान मंत्री जी से मिले हैं, हम से मिले हैं। उन्हीं आंकड़े इकट्ठे किए हैं। अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूं। —खगड़िया में 6 आदमी मरे हैं और 80 आदमी आहत हुए हैं...

श्री राम सेवक यादव : उन आंकड़ों को सही न मानिए।

श्री भजन लाल : आप कलेक्टर कहें, एस.डी.ओ. कहें वहां का ब्लाकवेयर कहे, एक-एक गांव में जाकर पूछता हूं तो उसको हम कहां कहेंगे क्या? मैं आपसे ही बात कहता हूं। इसको छुपाने से क्या फिदे वाला है? आप मुख्य मंत्री रहे हैं मैं भी मुख्य मंत्री रहा। मैं आपको एक विचार दूं किसी को पिस्तौल का लायसेंस लेना था। उसने कहा कि तोप का लायसेंस चाहिए कलेक्टर ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों लिखा? उस ने कहा कि तोप का मांगा है तब जाकर आप पिस्तौल का देंगे। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स ज्यादा दिखाही मांगती हैं कम नहीं बताती हैं। आप जानते हैं नार्म्स के मुताबिक इसमें 5 हजार रुपये प्रति व्यक्ति भारत सरकार को देना पड़ता है मरने वाले के परिवार को सहायता के तौर पर और जो ज्यादा जख्मी हो जाते हैं उन्हें 2 हजार तक की सहायता दी जाती है। मार्जिन मनी स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। बिहार के पास सारे देश में सबसे ज्यादा मार्जिन मनी है। उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हैं, उस के पास साढ़े 32 करोड़ है और बिहार के मार्जिन मनी 33 करोड़ है क्योंकि वहां पर बाढ़ वगैरह या प्राकृतिक प्रकोप ज्यादा होते हैं। इसलिए पहले से इंतजाम किया हुआ है सरकार ने, क्योंकि यदि इस तरह से अचानक आपत्ति आ जाए तो तुरन्त फौरी तौर पर सहायता की जाये। तो यह आंकड़े मैं बता दूं कि—सहरसा में 34 आदमी मरे हैं और 84 जख्मी हुए हैं, मुंगेर में 11 मरे और 200 जख्मी, दरभंगा में 34 मरे और 479 जख्मी, मधुबनी में 90 मरे और 470 जख्मी, समस्तीपुर में 3 मरे और 16 जख्मी, नालंदा में कोई मरा नहीं 12 जख्मी, पूर्णिया में 2 मरे और 17 जख्मी, भागलपुर में 1 मरा और कोई जख्मी नहीं, मोतिहारी में 3 मरा और 14 जख्मी। टोटल 146 लोग मरे हैं और 1209 जख्मी हुए हैं। महोदय, यह बहुत दुख का विषय है। सारे देश को इस पर दुख हुआ है। बहुत जख्मी लोगों ने बात की है। एक आदमी ऐसा मिला जिसको हालत बहुत खराब थी। प्रधान मंत्री जी ने लोगों को स्पेशल सिचुएशन को देखते हुए हिदायत दी कि अगर इसका यहां इलाज न हो सके तो इनको हवाई जहाज से ले जाकर वहां इलाज करें। उस आदमी का सारा शरीर डिसइन्फेक्टेड जैसा हो गया था। उसके सिर, हाथों को छोड़ कर सारा शरीर ढंका हुआ है। मैंने कहा कि दवाई नहीं है। हम ने कोई बात छुपाई नहीं है। जो

[श्री भजन लाल]

स मने आया है, हम ने बताया है। आठ डाक्टरों की टीम दवाई लेकर वहां पहुंच गई है ताकि मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो और फौरी तौर पर उनका उपचार हो सके। इसके अलावा मकानों के बारे में कहा गया। आप जानते हैं कि मकानों की हानि के बारे में इतनी जल्दी तलाश कर पाना आसान नहीं है। वहां की स्टेट गवर्नमेंट यह देखेगी कि कितने मकानों को क्षति पहुंची है। भारत सरकार के नार्म्स बने हैं और वाकायदा उनके मुताबिक हम उनकी सहायता करेंगे। और इस तरह से आपने कहा कि एक सर्वदलीय समिति बनानी चाहिए। आप जानते हैं कि कुछ पैसा भारत सरकार देती है बाकी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। और स्टेट गवर्नमेंट का यह सब्जक्ट है और बड़ी अच्छी बात है और मैं तो कहता हूं कि अगर ऐसी समिति बनकर के आए और वहां के स्टेट गवर्नमेंट लोगों की सेवा कर सके तो बड़ी अच्छी बात होगी। हम स्टेट गवर्नमेंट से कहेंगे कि उसे इसको बनाना चाहिए ताकि सब मिलकर के इस आपत्ति की घड़ी में लोगों के दुख में शरीक हो सकें।

श्री प्रमोद महाजन : क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने इस संभावना से इन्कार किया है ?

श्री भजन लाल : प्रधान मंत्री ने कोई इन्कार नहीं किया है, उन्होंने यही कहा है कि स्टेट का मामला है, स्टेट को देखना चाहिए।

ठाकुर जगतपाल सिंह : आप किसी की मदद करने को जाएं, तो कोई इन्कार नहीं करेगा।

श्री प्रमोद महाजन : प्रधान मंत्री ने, सर्वदलीय समिति की जरूरत नहीं, ऐसा कहा है।

श्री भजन लाल : देखिए, स्टेट का मामला है, प्रधान मंत्री ने इस बारे में बिल्कुल नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि स्टेट का मामला है, स्टेट देखेगी।

आपने जहानाबाद का भी जिक्र किया। जहनाबाद के बारे में प्रधान मंत्री ने फिर कल कहा है कि हम ऐसा कानून भी बनाएंगे, अगर जरूरत हुई तो, ताकि किसी जगह किसी हरिजन, आदिवासी के साथ इस प्रकार की दर्दनाक घटना नहीं घटे। उसके लिए पूरी भारत सरकार की कोशिश होगी और कानून बनाना पड़ेगा तो कानून भी बनाएंगे इसको भी प्रधान मंत्री जी ने कहा। एक बात आपने कही कि यह बयान भी आपका राजनीतिक है। कुछ ऐसे सियासी आदमी यहां आते हैं जो कागजी पहलवान कहूं, या हवाई बातों में यकीन रखते है। अगर आप फील्ड में जाते, तह में जाते तो आपको पता लगत इसमें क्या राजनीति है, क्य हमने छिपाया है ? क्या राजनीतिक प्रचार है इसमें ? कम से कम यह सदन है और इसमें बाहर लिखा हुआ है कि या तो सदन में प्रवेश नही करें, प्रवेश करें तो सत्य बोल, झूठ नहीं बोले। आपको यह बात कहनी शोभा देती है कि यह राजनैतिक स्टेटमेंट है ? राजनीतिक स्टेटमेंट नही है यह। हम कुछ नही कहते, हम तो आपका सहयोग चाहते हैं। सबने इस दुख की घड़ी में, मिलकर के इस दुख की घड़ी का मुकाबला करना है।

जहां तक आपने वहां कानून जीवन के बारे मे, वह तो आ गया, कि आप दिखा रहे हैं। वहां के मुख्य मंत्री कम दिखा रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा मुख्यमंत्री को कम नहीं दिखाते। मैं कहता हूं कि कोई भी मुख्य मंत्री ऐसा नही, जहां सूखा पड़ गया हो, बाढ़ आ गई हो वह कम दिखाये। वह दिखायेगा कि ज्यादा यहां नकसान हुआ है ताकि ज्यादा से ज्यादा मिल सके।

आपने कहा कि बर्ज दिलाने के बारे में बकाया मोरिल दि व जीवे, प्रधान मंत्री जी ने लिखे हैं कि हुडको से बकायदा ऋण की व्यवस्था की उन लोगों के लिये। सरकार से जो सहायता मिलनी है, वह सारी सबसिडी सरकार भी देगी और इन्सटालमेंट्स 22 साल में वसूल करने के साथ और सिर्फ 7-परसेंट ब्याज लेकर के उन लोगों की यह की सहायता दी जायेगी ताकि वे लोग कर्जा लेकर के अपने मकान भी बन सकें

शिवाजी ने कहा कि वक्तव्य देरी से दिया गया । वक्तव्य देरी से नहीं दिया गया । परसों सुबह का वाक्या है, कल प्रधानमंत्री और सारे उनके साथी और मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं सब मौके पर पहुंचे और जाकर के एक-एक बात को देखा और बाकायदा वहां शिविर लगे हुये हैं, कैम्प लगे हुये हैं जहां बाकायदा लोगों के खाने का इंतजाम किया हुआ है ।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी (आंध्र प्रदेश) : किनकी तरफ से इंतजाम किया गया है ?

श्री भजन लाल : वहां की स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पूरा इंतजाम किया गया है । बाकायदा डाक्टरों की टीम वहां पहुंची हुई है, पूरी रिलीफ का काम वहां चला हुआ है ताकि लोगों की पूरी देखभाल की जा सके ।

भट्ट साहब ने ठीक कहा कि रेडियो पर जो बात आई है कि सरकार की तरफ से जो पक्ष है वह 164 बताता है और गैर सरकारी रेडियो बहत्तर है चार सौ । यह ठीक बात है कि चाहे रेडियो हो, चाहे अखबार हो या टीवी० हो, जो बात ठीक है वही कहनी चाहिये, वही उनको भी कहनी चाहिये । जो ठीक न हो उसको नहीं लिखना चाहिये । मैं यह नहीं कहता कि प्रेस इसके लिये दोषी है, लेकिन जितना ज्यादा नुकसान हुआ उससे अनुमान गलत हो सकते हैं । कल ही कम से कम पचास अखबार वाले प्रधानमंत्री के प्रेस कांफ्रेंस टना में मौजूद थे, उनके सामने सारी बातें ई ।

इसके साथ ही दूसरी रियायतों के बारे में कहा गया । मैं बतलाना चाहता कि मार्जिन मनी सभी प्रांतों में मौजूद । 1988-89 में 245 करोड़ रुपया ी स्टेटों को दिया हुआ है भारत सरकार तरफ से । उसमें आधा पैसा भारत कार का है और आधा स्टेट गवर्नमेंट है ताकि फौरी तौर पर लोगों की मदद हो सके । श्री गोपालसामी ने कहा कि नेपाल वाले ज्यादा बता रहे है मृतकों की संख्या, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ज्यादा नहीं बताते । उन्होंने कहा कि 16 घंटे तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । साढ़े चार या पौने पांच बजे का यह वाकया है और ज्यों ही पता लगा, मुख्य मंत्री वहां पहुंच गये, शाम तक सारी रिपोर्ट लेकर भारत सरकार को दी और सुबह प्रधान मंत्री और हम सब लोग वहां गये । आपने कहा कि वहां बांध बने हुये हैं इससे भूकम्प आते हैं । यह बात नहीं हो सकती, अगर ऐसा होता तो और दूसरे मृतकों में तो बहुत ज्यादा बांध हैं, वहां ज्यादा तबाही होती और इससे ही अगर भकम्प आते तो भाखड़ा-नंगल बांध से हिमाचल प्रदेश अब तक डूब गया होता ।

हमारे प्रमोद महाजन जी ने कहा कि भारत 2.5 सेंटीमीटर हर साल सरकता हिमालय की तरफ है । अगर ऐसा होता तो जो हिमालय के पास गांव हैं वे अब तक धंस गये होते । हिमालय सरकता नहीं है, ऐसे मैं नहीं कहता, हमारे शास्त्र कहते हैं कि हिमालय की तरह अडिग टिकाऊ और मजबूत रहन चाहिये । हिमालय चलता नहीं है । ये सब हवाई बातें है जिनमें कोई सार नहीं है । थोड़ा बहुत कुछ होता होगा नहीं तो भूकम्प कैसे आता ?

श्री प्रमोद महाजन : थोड़ा बहुत लंका की ओर भी जाता होगा ।

श्री भजन लाल : कौन हिमालय के नीचे दब है अब तक ?

श्री भट्टाचार्य ने कहा कि नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया, कब तक अंदाजा लगायेंगे । जैसा मैंने पहले कहा अंदाजा वहां की स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है, उसने बाकायदा अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है, उनके अधिकारियों से हमारे कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि एक एक चीज की जानकारी दें कि कितनी सड़कें टूटी हैं, कितने अस्पतालों की इमारतें गिरी हैं । पशुओं के बारे में कहा गया कि बहुत से मरे । आप ये तो किसान के घर में पैदा नहीं हुए या पशु नहीं रखते ।

[श्री भजन लाल]

आप नहीं जानते कि गर्मियों में पशुओं को घरों के अन्दर यानि मकानों में नहीं रखा जाता, उमस बहुत होती है, हां सर्दियों में घरों के अन्दर उनको बांधा जाता है। बरसात में भी रात को बाहर बांधते हैं। उनको गर्मियों में अन्दर यानि मकान में बांधने का सवाल ही नहीं है।

श्री राम नरेश यादव : आपको जानकारी नहीं है, घरों के अन्दर बांधते हैं।

श्री भजन लाल : यहां दिल्ली में गाय या भैंस बांधी होगी। पशुपालक होते या किसान होते तो ऐसी बात न कहते।

श्री राम चन्द्र विकल : दीवार के साथ बांधे हों तो दीवार गिरने से मर सकते हैं।

श्री भजन लाल : हां यह हो सकता है।

आपने कहा कि प्रधान मंत्री जी पैदल क्यों नहीं गये। प्रधान मंत्री जी पैदल चल चल कर बहुत से कस्बों में और महल्लों में गए और लोगों की हालत वहां जाकर देखी। यहां दिल्ली के एयर कंडीशन में बैठकर यह कह देना कि प्रधान मंत्री जी कहीं पैदल नहीं गये, यह ठीक नहीं। बाहर से लोगों ने आकर उनको अपनी तकलीफें सुनाई। बहुत से छोटे एरियाज हैं, दरभंगा को बहुत बड़ी जगह नहीं है। सबकी बातें सुनकर प्रधान मंत्री जी ने मुख्यमंत्री बिहार के जिम्मे लगाया कि शीघ्रातिशीघ्र सहायता दें। भूकम्प की रक्षा कैसे करनी चाहिये, इसका पता पहले से लगना चाहिये इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बारे में पहले से पता लगाना बड़ा मुश्किल है। रक्षा जहां तक हो सकती है इंसान को वह करनी चाहिये और हम करते हैं।

रजनी रंजन साहू जी ने कहा सही संख्या क्या है और डाक्टरों की टीम भेजी या नहीं। जैसा मैंने बताया कि 8 डाक्टर यहां से गये हैं। प्रदेश सरकार के अपने भी डाक्टर हैं। अगर भारत सरकार से डाक्टरों की जरूरत पड़ेगी तो स्पेशल हवाई जहाज से भी अगर भेजना पड़ेगा तो हम भेजेंगे ताकि लोगों का उपचार ठीक ढंग से हो सके। विकल साहब ने जो कहा उसका जवाब दिया जा चुका है।

वेस्ट बंगाल और असम में क्या नुकसान हुआ इसके बारे में भी जानना चाहा। कल सुबह वेस्ट बंगाल के मुख्य मंत्री जी से मेरी बात हुई ठीक सवा आठ बजे और असम के मुख्य मंत्री से साढ़े आठ बजे बात हुई। उन्होंने कहा यहां भूकम्प का झटका जरूर आया, लेकिन जानी नुकसान किसी का नहीं हुआ यहां माननीय सदस्य बैठे हुए हैं बंगाल के भी और असम के भी। किसी ने इस बात की चर्चा नहीं की कि ऐसा कोई जानी नुकसान हुआ है। हां थोड़े बहुत मकान का नुकसान हो सकता है या दार्जिलिंग के बारे में पता लगा कि थोड़ी बहुत वहां मकानों की क्षति हुई है ज्योंही हमारे पास जानकारी आयेगी, स्टेट गवर्नमेंट ज्यों ही सूचना भेजेगी कि इतना नुकसान हुआ है हम बाकायदा भारत सरकार की स्पेशल टीम सेंट्रल टीम भेजेंगे जो एक-एक बात को देखेगी और जो सहायता उनकी हम कर सकते है, उनके मुताबिक पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे।

जेटमलानी जी ने कहा कि साढ़े सात बजे रेडियो से कुछ नहीं बताया गया ऐसा है कि पांच बजे यह वाकया हुआ तो साढ़े सात बजे रेडियो पर आना संभव नहीं था क्योंकि यह बहुत इंटीरियर में हुआ पटना शहर में कोई वाकया नहीं हुआ है डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में कुछ हुआ है लेकिन इंटीरियर में जा कर पता लगाने में समय लगता है इसलिये साढ़े सात बजे रेडियो में इसकी सूचना नहीं दी गयी। लेकिन इसके बाद तो रेडियो, टेलीविजन और अखबारों ने इसकी सारी खबर पूरी दी। काफी बढ़ा-चढ़ा कर, दुगनी, तिगुनी बढ़ा-चढ़ा कर कर बात कही है।

बांध के नुकसान के बारे में भी पूछा गया। मैं प्रधान मंत्री जी के साथ गया और एक-दो बांध का सर्वे किया। एक बांध को देखा है। हेलीकाप्टर बहुत नीचे ले जाकर देखा कहीं कोई बांध टूटा हुआ नहीं दिखाई दिया कहीं छोटी नदी जिसकी बहुत कम

पटरी होती है और बरसात के दिनों में कच्ची पटरी थोड़ी बहुत टीप करने लग जाती है, यह कुछ करने वाली हो तो इसका इन्तजार नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी को तुरन्त होने को कहा नहीं।

यह भी कहा गया कि ग्रामों के लोग शहरों में क्यों आये। आप जानते हैं जब उन्हें पता लगे कि प्रधान मंत्री जी आ रहे हैं तो यह बहुत बड़ी बात होती है और जेठमलानी जी तो लोगों के लिए भी काफी वकील इकट्ठे हो जाते हैं। ग्रामीण लोगों को तो यह पता लगा कि प्रधान मंत्री आ रहे हैं, क्योंकि पहले दिन से एनाउन्समेंट हो रही थी रेडियो, टेलीविजन और अखबारों में तो वे अपनी बात कहने के लिए इकट्ठे होंगे। प्रधान मंत्री जी ने ग्रामीण भाइयों, बहनों, बूढ़ी औरतों की एक-एक बात बड़े ध्यान से सुनी और सहायता जो उनकी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को आदेश भी दिये ताकि किसी प्रकार की लड़ाई बाकी न रहे।

ठाकुर जगतपाल सिंह : बाढ़ और सूखा के बारे में तो...

श्री भजन लाल : इन्हें तो पक्का पक्काया मिल गया है ठीक है। इनको पकाने की क्या जरूरत है।

श्री यशवंत सिन्हा : आप ऐसी गम्भीर बात डिसकस कर रहे हैं तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। This is a very serious matter and this is not the attitude you should adopt.... *(Interruptions)* ...

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): You are only sitting here. You have not identified yourselves with the people ...*(Interruptions)*...

श्री भजन लाल : जहां तक गैर सरकारी संगठनों की मदद की बात है मैं कहना चाहता हूं कि वे लोग भी बाकायदा मिले हैं और उन्होंने मदद करने की बड़ी इच्छा जाहिर की है। जब ऐसी कोई मुसीबत आती है, सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है या ऐसी कोई भूकम्प वाली स्थिति होती है तो ये संगठन हमेशा मदद करते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। और भी कोई महानुभाव मदद करना चाहे तो उनका भी स्वागत है। सरकार उनके साथ हमदर्दी रखती है जिनका इसमें नुकसान हुआ है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी इस संकट की घड़ी में इन लोगों के लिए नहीं रहने दी जायेगी। जिसकी जरूरत होगी वे सारी चीज उन्हें मुहैय्या कराई जायेंगी। जिन चीजों की जरूरत होगी वे सारी चीजें उनको मुहैय्या कराई जायेंगी, किसी प्रकार की दिक्कत हम उनको नहीं आने देना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम चन्द्र विकल : जापान के वैज्ञानिकों ने इस संबंध में काम किया है इसके बारे में आपका क्या कहना है?

श्री भजन लाल : आपने कहा है कि जापान ने इस संबंध में स्टेडी की है उसको भी दिखवा लेंगे। जापान ने इस संबंध में जो कुछ किया है उसके बारे में भी पूरी जानकारी कर लेंगे। लेकिन हमारे वैज्ञानिक भी किसी से पीछे रहने वाले नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : आपने जो मृतकों की संख्या अपने वक्तव्य में बताई है वह 164 बताई और घायलों की संख्या 1209 बताई है। यह सूचना कल रात बिहार सरकार ने दी है उसपर आधारित है। आमतौर पर सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इसके अलावा सूचना कि क्या कोई और मारे गये हैं, या किसी की और मृत्यु हुई है तो इसकी भी सूचना सदन को दी जाय। चूंकि सदन 5 सितम्बर तक चलने वाला है, इसलिए सदस्यों की आम भावना है कि इसपर पुनः आप सदस्यों को बता दें।

श्री भजन लाल : उपसभाध्यक्ष महोदय, जो भी लेटेस्ट सूचना आएगी, सदन को जरूर अवगत कराया जाएगा और इस

[श्री भजन लाल]

वक्त जो सूचना हमारे पास है वह यही है और सही है ।

ठाकुर जगतपाल सिंह : श्रीमन्, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं । उधर के माननीय सदस्यों ने कहा कि इस तरह की नेचुरल कैलेमिटीज के वक्त मदद करना चाहिए । मैं जानना चाहता हूं कि वे किस तरह की मदद करना चाहते हैं ? आप वहां क्यों नहीं जाते हैं ? वहां जाइए और लोगों की मदद कीजिये । आपको सेवा करने से कौन रोक रहा है ?

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) अब हम परिनियत संकल्प पर पुनः विचार शुरू करते हैं । श्री एम० हनुमंत राव ।

I. Statutory Resolution seeking disapproval of the National Security (Amendment) Ordinance, 1988

II. National Security (Amendment) Bill, 1988—Contd.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, it is very unfortunate that we have, immediately after discussing this ghastly tragedy of the earthquake, to discuss this National Security Act which is man-made and a man-made calamity also. I stand to oppose this amendment as well as the original Act itself. It is sought to be made out that it is a very simple thing: to extend it by one year. I am opposed to this because it is a Draconian Act which has been there on the Statute Book almost ever since our independence. It is so much identified with the Congress rule in the past, and the present Congress (I) rule also is continuing it, except for a brief period of one or two years when Shrimati Indira Gandhi could not get the required majority; except that period it has been all through there and also except when she was thrown out of power and the Janata Government came into power.

[The Vice-Chairman (Shri H. Hanumanthappa) in the Chair]

So, Sir, this is a most undesirable Act which is against the Fundamental Rights which are given by the Constitution. And it has been practised by the Congress Government as if it is a normal thing. It is an unfortunate thing. The hon. Home Minister says that it would be extended only by a year and as soon as it is possible it would not be there on the Statute Book. That has not been so. The experience shows that the Congress Government could never get on without this repressive measure being there. Very frequently, most of us have been victims of either the Preventive Detention Act or of the National Security Act or some other Act. This repression is very much identified with the Congress rule. It is such a draconian law that nobody desires it. Although we are all the time saying that it is the most democratic country, we are actually living in a real police state. That is the actual practice.

Although the Act is being amended in the name of Punjab, it has got all-India repercussions also. It is an amendment to an all-India Act which hangs on us as a democles sword. So, naturally, automatically, it may be extended to all the States at any time. That is the fact of this democracy. It is now being presented in the name of Punjab. It is being argued that there is an extreme circumstances prevailing and that is why the Government has brought in such a measure. That is what is stated here. Although there were no disturbances in the past or there were no disturbing events as in Punjab today anywhere, this law has been kept always on the Statute Book. So, to say now that it is only in the case of Punjab or that it is in the context of Punjab that it has been brought forward is not true.

Another thing that I want to bring to your notice, Mr. Vice-Chairman, is that many trade union leaders have been repeatedly detained under this National Serity Act. That means that it has been misused awfully and repeatedly. Not only that, if we take the case of Tamil Nadu where the President's rule is there, just on the eve of Bharat Bandh, i.e. March 15, almost 30,000 people were taken into